

गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन उत्कृष्ट है: नये-नये तरीके ढूँढ़े गये चहेती कंपनियों से लूट मचवाने के लिए

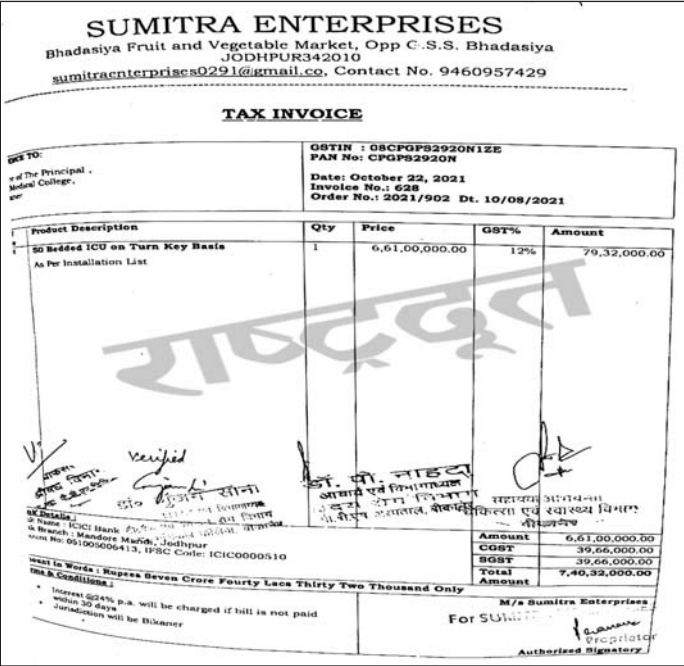
उदाहरण के लिए, एसएमएस अस्पताल को अधिकृत किया गया, राज्य के सभी अस्पतालों के लिये वैंटीलेटर खरीदने के लिये

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 21 अप्रैल। गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी के चलते स्टेट डिज़ास्टर रिस्केशन फंड (एस.डी.आर.एफ.) से आई.सी.यू. इत्यादि जैसे स्थाई निर्माण ही नहीं किये गये, बल्कि चिकित्सा विभाग के वित्त सलाहकारों ने नियमों की अनदेखी करते हुए इन आई.सी.यू. व बच्चों के लिये बने एन.आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों को “टर्नकी” प्रोजेक्ट की तर्ज पर शुरू करने की अनुमति भी दे दी, जिसके कारण इन आई.सी.यू. में लगाये जाने वाले उपकरणों की खरीद में भी भारी धांधली हुई।

दरअसल कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद पर केन्द्र सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी, इसके तहत जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई थी, परंतु यह छूट टर्नकी प्रोजेक्ट्स पर लागू नहीं की जा सकती। पर हैरानी की बात है कि एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ने पूरे प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में वैंटीलेटर, ई.सी.जी. मशीन, वॉर्मर इत्यादि खरीदे लेकिन महंगी दरों पर और सप्लायरों की तरफ से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी अदा किया।

यही नहीं एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति ही पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिये मेडिकल उपकरण खरीद के आदेश दे रही थी, जबकि उन्हें किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओर से



प्रकाशित दस्तावेज एक टैक्स बिल है जिसमें देखा जा सकता है कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज में सुमित्रा एन्टरप्राइजेज नामक एक फर्म से 50 बिस्तर के आई.सी.यू. में “टर्नकी प्रोजेक्ट” के माध्यम से मेडिकल उपकरणों को लगाने का अनुबंध किया गया था। इस कंपनी द्वारा मेडिकल उपकरण लगाने के लिये मेडिकल कॉलेज से 12 प्रतिशत की दर पर जी.एस.टी. वसूला गया। जैसा कि विदित है कि कोविड के दौरान केन्द्र सरकार ने मेडिकल उपकरणों की खरीद पर जी.एस.टी. की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी थी, परंतु गहलोत सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियम और नीति के विरुद्ध जाते हुए एस.डी.आर.एफ. से घटिया दर्जे के आई.सी.यू. का निर्माण कराया और मेडिकल उपकरण की खरीद में भी भारी धांधली की।

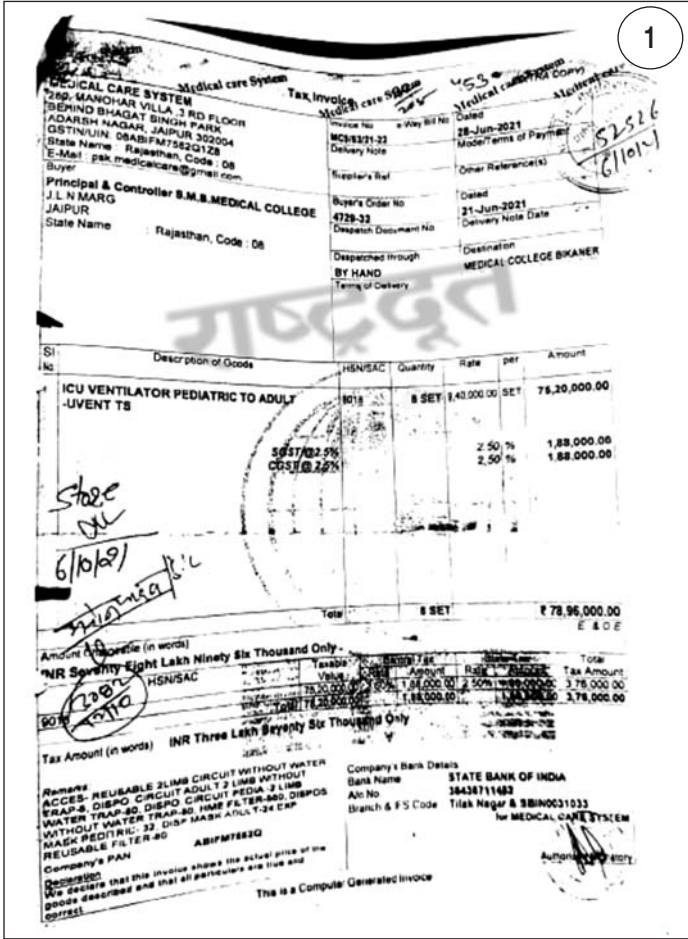
पर, किस अस्पताल को कितने वैंटीलेटर चाहिए अपने आईसीयू के लिए, इस बारे में अस्पतालों से न तो पूछा गया और न ही कोई बातचीत की गई।

जैसा कि खबर के साथ प्रस्तुत बिलों की प्रतियों से नज़र आता है। एसएमएस अस्पताल के लिये जिन दामों पर वैंटीलेटर खरीदे गये, उससे लगभग दोगुने दामों पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों के लिए वैंटीलेटर खरीदे गये, यह एक्स्ट्रा पेमेंट किस को मिला?

वैंटीलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी को जीएसटी का पूरा लाभ दिलाने की दृष्टि से वैंटीलेटर केन्द्रीय सरकार की नीति व आपदा प्रबंधन निधि से खरीददारी नहीं की गई। अगर केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था के अनुसार खरीद की जाती तो जीएसटी 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत ही लगती। ऐसे “सुप्रबंधन” के कई नायाब तरीके ढूँढ़े गये और सप्लायर को लाभान्वित किया।

गहलोत सरकार के अधिकारी कुछ गिनी चुनी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद का बल्क ऑर्डर ना देके अलग-अलग खरीद के आदेश पारित कर रहे थे। इसका स्पष्ट प्रमाण एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस पी मैडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। जहां एक ओर वैंटीलेटर 9 लाख रुपये की दर पर खरीदे गये वहीं दूसरी ओर लगभग दुगुनी लागत पर खरीदे गये।

उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव नहीं सौंपा गया था। हालांकि यह भी सत्य है कि महामारी के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये निविदा जारी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम निर्बंधित था परंतु राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मेडिकल उपकरणों की खरीद आर.एम.एस. सी.एल. के माध्यम से की जा सकती थी। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



लालू-राबड़ी व नीतीश का युग समाप्ति की ओर अग्रसर

पोप फ्रांसिस का निधन



वैटिकन, 21 अप्रैल। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का ईस्टर सोमवार को वैटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। होली सी (रोमन कैथलिक चर्च की

88 वर्षीय पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के कासा सांता मार्टा में अपने निवास पर अंतिम सांस ली।

सरकार) ने आज यह जानकारी दी। होली सी ने एक्स पर लिखा, पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर सोमवार को 88 वर्ष की आयु में वैटिकन के कासा सांता मार्टा में उनके निवास पर हुआ। वैटिकन के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा से हिन्दुस्तान के लिए खिड़की तो खुली, ट्रम्प तक बात पहुंचाने के लिए

इस समय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन व चीन, दोनों से “लगभग” शत्रुता के रिश्ते बनाये हुए हैं और बातचीत बंद सी है। अतः भारत के पास अपना पक्ष सुनाने का अच्छा मौका है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की आज की भारत यात्रा, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है।

सबसे पहले, इस यात्रा में एक व्यक्तिगत पहलू है, जो उनकी पहली यात्रा के बारह साल बाद हो रही है। इस व्यक्तिगत जुड़ाव के बयान के साथ, वैंस की भारत यात्रा इस बात को स्पष्ट करती है कि वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत में अपने शुरुआती कार्यक्रमों के तहत, उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया, जहाँ वैंस के बच्चों ने भारतीय परिधान पहन रखे थे और उनके गले में फूलों की मालाएँ थीं। इससे अमेरिका की “सैकण्ड फैमिली” और भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यक्तिगत

पर, जैसा ट्रम्प का स्वभाव है, अगर इनमें से किसी से भी बातचीत शुरू हुई तो ट्रम्प भारत का साथ छोड़कर, इन दोनों से सौदेबाजी शुरू कर देंगे, क्योंकि अपने साइज़ व आर्थिक ताकत के कारण, ये दोनों भारत से ज्यादा महत्व रखेंगे, ट्रम्प की निगाह में।

संबंधों का गहरा संकेत मिला।

दूसरा संकेत मिला कि भारत, अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश को एशिया में तथा समग्र भू-राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक मजबूत दीवार के रूप में देखा जाता है। अमेरिका चीन को अपना प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मानता है, आर्थिक रूप से भी और रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी। गौरतलब है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक लंबे दौरे पर हैं, जहाँ वे एक ऐसा राष्ट्र-गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका के विरुद्ध चीन के साथ खड़ा हो सके। अभी हाल तक, दक्षिण-

पूर्वी एशियाई देश लगभग अमेरिका के सहयोगी देश ही माने जाते थे। अब चीन इन देशों को, चीन के विशाल बाजारों में आकर्षक सुविधाओं का लालच देकर अमेरिका से दूर करने की कोशिश कर रहा है। चीन इन देशों को यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका की तुलना में वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर है। इस तरह से, चीन एशिया में, और अन्य जगहों पर भी, अमेरिका को उसके सहयोगियों से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। कई मायनों में, अमेरिका पहले से ही वैश्विक मंच के प्रमुख खिलाड़ियों से थोड़ा अलग-थलग हो गया है। ट्रंप

प्रशासन ने चीन और यूरोपीय संघ, जो आर्थिक और रणनीतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्लाक हैं, को बुरी तरह आहत किया है।

वैंस बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जैलेंस्की के साथ डॉनबेड ट्रंप की कुख्यात बैठक में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वैंस, ट्रंप के विश्वासपात्र हैं, हालांकि, ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री को यात्रा के दौरान वैंस को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस प्रकार, भारत के पास यह अवसर है कि वह अमेरिका को अपनी स्थिति समझा सके, खासकर ऐसे समय में, जब अमेरिका ने अपनी टैरिफ की बाढ़ के जरिए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ एक प्रकार का व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। भारत को भी तथाकथित “रैसिप्रोकल टैरिफ” का सामना करना पड़ा है, जिसे वर्तमान में 90 दिनों के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेल प्रहरी पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं मिली

जयपुर, 21 अप्रैल। जयपुर मेट्रो-प्रथम की डीजे कोर्ट ने जेल प्रहरी भर्ती-2018 के पेपर लीक मामले के आरोपी करन कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए, आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। डीजे नंदिनी व्यास ने फैसले में कहा कि मौजूदा मामले में

अदालत ने कहा, आरोपी लंबे समय से अनुसंधान के लिये उपस्थित नहीं हो रहा है, इसलिये जमानत नहीं दी जा सकती।

आरोपी को लंबे समय से अनुसंधान के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई, जिस कारण केस के अनुसंधान में भी देरी हुई है। मामला सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम व अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ा है और ऐसे मामले के आरोपी को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की भारत यात्रा से वाशिंगटन की टैरिफ नीति पर नई दिल्ली की चिंताएँ कम होंगी? बीजिंग का कहना है, ऐसा नहीं होगा। बीजिंग ने यात्रा के परिणामों और उद्देश्यों को बहुत हल्के रूप में लिया है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, वैंस की चार दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के बीच के आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बीच हुई है। लेकिन भारत और चीन के विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि इस यात्रा से अमेरिका के कथित “रैसिप्रोकल टैरिफ” पर भारत की चिंताओं में कोई राहत नहीं मिलेगी और न ही इससे भारत की व्यापार नीति में कोई निर्णायक बदलाव होगा। अपनी अधिकृत कृतीति की “पर्सनल टच” देते हुए, वैंस अपनी पत्नी ऊषा वैंस, जो हिंदू हैं और बच्चों के साथ

दौर के बाद, ऐसी संभावना हो सकती है कि आगामी चुनावों के बाद, बिहार में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘वैंस की भारत यात्रा से हिन्दुस्तान की टैरिफ संबंधी चिंताएँ घटेंगी नहीं’

चीन के प्रमुख समाचार पत्र, ग्लोबल टाइम्स तथा चीन के नैशनल स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट का मानना है, दोनों देशों की वाणिज्य नीतियों में सामंजस्य बैठना संभव नहीं

■ अमेरिका के टैरिफ वॉर का मकसद है, अमेरिका में काम आने वाली ज्यादा से ज्यादा चीज़ें अमेरिका में ही निर्मित हों तथा अमेरिका विश्व का “मैन्यूफैक्चरिंग हब” (औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र) बने।

■ दूसरी ओर भारत का “मेक इन इण्डिया” का सोच भी, हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की दिशा को ही सही मानता है।

■ अतः, उपराष्ट्रपति वैंस की भारत यात्रा एक गुडविल (सद्भावना यात्रा) तक ही सीमित रहेगी और कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा, भारत को “टैरिफ वॉर” में।

मत है कि यह यात्रा सावधानीपूर्वक तैयार की गई सोची समझी रणनीति है, जिसमें

कारण यूएस के अपने सहयोगियों के साथ उपजे तनाव के समय में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना है, लेकिन बीजिंग में कुछ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा भारत को अनुसूछे टैरिफ विवाद से राहत देगी। शिन्हुआ विश्वविद्यालय के नैशनल स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट के निदेशक कियान फेंग का कहना है कि वैंस कई उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय ट्रेड पैक्ट से लेकर टैरिफ विवादों के हल तक पर फेंग ने चेतावनी दी कि ठोस नतीजे मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वाशिंगटन का सारा जोर व्यापार घाटा कम करने और निर्माण गतिविधियों को अमेरिका वापस लाने पर है। यह रणनीति “मेक इन

इंडिया” के खिलाफ है। हालांकि, कुछ प्रगति हुई है, जैसे 29 मार्च को अमेरिका के ट्रेड प्रतिनिधियों व भारत के वाणिज्य मंत्रालय के बीच 2030 तक व्यापार 500 बिलियन डॉलर पहुँचाने के लक्ष्य पर समझौता हुआ, पर अभी भी कई बाधाएँ हैं। इस पृष्ठभूमि में विश्लेषकों का कहना है कि वैंस संभवतः भारत को वाशिंगटन के उद्देश्यों के बारे में पुनः आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे तथा टैरिफ के लचीलेपन को प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, जो उसकी घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग में कटौती करे, तथा अमेरिकन टैरिफ नीतियों की प्रस्तावित रियायतों पर आँखें मूंद कर भरोसा करे। बीजिंग एकेडमी ऑफ सोशल साइन्सेज के एसोसिएट रिसर्च फैलो वांग पेंग ने कहा है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के टैरिफ-जन्य तनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ सीबीआई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में हरीश के खिलाफ जाँच के आदेश दिये।

मुठभेड़ और प्रजापति की हत्या का केस सीबीआई को सौंपा था। सवाल यह है कि क्या यह गहलोत की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आखिरी जीत है। इसी सीबीआई कोर्ट ने इस प्रकरण में हरीश चौधरी, उनके भाई मनीष चौधरी और 24 आईपीएस अफसर सहित, 24 पुलिस अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रजापति हत्याकांड में हरीश चौधरी का नाम?

विचार बिन्दु

हमारे कष्ट पापों का प्रायश्चित है। –हज़रत मोहम्मद

सर्वोच्च न्यायालय पर इतना आक्रमण क्यों?

भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। 2022 में जब से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने हैं, वे निरंतर अपने विवादास्पद व्यवहार और बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। इससे पूर्व जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई प्रकार के विवादों में उलझे रहे। अपने बयानों के द्वारा वे राज्य सरकार के काम करने के तरीके पर कटाक्ष करते रहे और सर्वजनिक रूप से भी राज्य सरकार की बहुत आलोचना करते रहे। राज्यापालों से अपेक्षा यह की जाती है कि वे सवैधानिक पद पर होने के कारण, अपनी राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर निष्पक्ष और संवैधानिक मर्यादा के अनुसार कार्य करेंगे। संभवतया, राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार के कामकाज में उन्होंने जिस प्रकार केंद्र के इशारे पर रोड़े अटकाए, उसी को देखते हुए, भाजपा के नेतृत्व ने उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर अपना उम्मीदवार बनाया और बहुमत के आधार पर वे इस पद पर आसीन भी हो गए।

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। गत 3 वर्षों में, अनेक बार यह देखा गया है कि उन्होंने सभापति के रूप में पक्षपात पूर्ण कार्य करते हुए विपक्षी नेताओं को बार-बार टोका। एक बार तो उन्होंने अनेक सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता से निर्लंबित भी कर दिया। उनका पक्षपात पूर्ण व्यवहार, टीवी पर राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के माध्यम से पूरे देश ने कई बार देखा है। विपक्षी दलों ने तो एक बार उनके व्यवहार से धुंध होकर उनके विरुद्ध अविवश्या प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, किंतु उपसभापति ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य करते हुए अपने पदों की गरिमा को तार-तार कर दिया।

हाल ही में उनका सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में दिया गया बयान तो सारी सीमाओं को पार कर गया। इसके कारण मीडिया में गत तीन चार दिन से उनकी आलोचना हो रही है। यह वक्तव्य उन्होंने राज्यसभा के प्रशिक्षु इन्टरन के बैठ को संबोधित करते हुए दिया था। उन्होंने कई प्रकार के आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाते हुए कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर की सुपर संप्रसेस की तरह मानी है।” वह संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग परमाणु मिसाइल की तरह करती है जिससे लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की कोई जवाब देही नहीं है। उन्होंने इस अवसर पर न्यायाधीश वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिलने की बात का भी उल्लेख किया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज न करने पर भी आक्षय व्यक्त किया। यह सही है कि न्यायाधीश वर्मा के बारे में हो रही जांच में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में कोई जानकारी सर्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की कार्रवाई को वेबसाइट पर सर्वजनिक करने का साहस अवश्य दिखाया है। यह आशा की जा सकती है कि जस्टिस वर्मा के विरुद्ध संवैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई संभव है वह शीघ्र की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए निर्णय को अवहेलना हुई है। इससे कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। कानून बनाने का काम संसद का है न कि सर्वोच्च न्यायालय का। इस प्रकार के बयान देने समय उपराष्ट्रपति यह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी कानून बनाया नहीं, अपितु जब भी संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान के विपरीत था तो उसे निरस्त करने का संवैधानिक दायित्व निभाया। ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही किया।

यह भी एक विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य उच्च सत्ताधारी नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उस समय प्रशंसा करते हुए नहीं थकते जब कोई निर्णय सरकार के पक्ष में हो जाता है। उदाहरण के लिए जब राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सर्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए न्याय की सराहना की।

उपराष्ट्रपति जब विधायिका के सम्मान की बात करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की होती तो विधानसभा में चुने हुए विधायकों द्वारा पारित कानून का क्या हश्र होता? तमिलनाडु विधानसभा के 10 विधेयक, पारित होने के बाद भी राज्यपाल के पास अनिश्चितकाल तक पड़े रहे और बाद में राष्ट्रपति के पास विचार दिए भेज दिए गए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।

यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान हैं अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने इस बात पर हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि “यह क्या हो रहा है और इसका क्या परिणाम होगा?” वास्तव में उन्होंने सही कहा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन यह बात उनके द्वारा किए गए व्यवहार के ऊपर अधिक सही लागू होती है न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए व्यवहार के ऊपर। कल्पना कीजिए यदि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकरणों में दखल नहीं देता, तो क्या होता:—

इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह वहां के पीएसवी अधिकारी अश्लि मसीह ने भाजपा के पक्ष में कार्य करते हुए अवैतिक रूप से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, दखल नहीं देता, तो क्या होता:— इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया जाता। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जिस तरह वहां के पीएसवी अधिकारी अश्लि मसीह ने भाजपा के पक्ष में कार्य करते हुए अवैतिक रूप से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, दखल नहीं देता, तो क्या होता:—

उसे निरस्त नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में बुलंदशेर के माध्यम से गरीबों के मकान गैर कानूनी रूप से बिना नोटिस के ध्वस्त करने के आदेशों पर यदि सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता।

यदि सुप्रीम कोर्ट समुचित आदेश नहीं देता तो यही लगता कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान की रक्षा नहीं कर रहा है। उपरोक्त कुछ प्रकरणों से तो यही स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल संविधान सम्मत कार्य किया है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में से कौन बड़ा है, यह प्रश्न ही बेमानी है। न संसद बड़ी है न न्यायपालिका। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता नागरिकों की होती है और उसी को बनाए रखने के लिए संविधान बना है। अतः, सर्वोपरि तो संविधान है और शासन के सभी अंगों को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। जब कभी नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों पर कार्यपालिका द्वारा प्रहार होता है तो, सामान्य नागरिक सदैव सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखते हैं।

वक्क संशोधन कानून पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के एक दिन पूर्व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू ने लगभग चेतानी भरे शब्दों में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार कोर्ट के काम में दखल देना प्रारंभ करे, तो उसे कैसा लगेगा? यह प्रोक्ष रूप में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने जैसा ही वक्तव्य था।

वक्क संशोधन कानून पर बहस के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना द्वारा पूछे गए तोछे प्रश्नों का उत्तर सॉलिसिटर जनरल नहीं दे पाए और उन्होंने एक सप्ताह का समय उत्तर देने हेतु मांगा। न्यायालय के इस रुख से सरकार में बड़ी खलबली मची हुई है। मजबूत सरकार को यह आश्वासन कोर्ट को देना पड़ा कि वह वक्क संशोधन कानून के बारे में कोई कार्यवाही आगामी तिथि तक नहीं करेगी।

उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगाया। ऐसा कहते समय उपराष्ट्रपति को यह याद नहीं रहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है।

कार्यपालिका या विधायिका के किसी निर्णय को संवैधानिक समीक्षा करने का अधिकार, संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को दिया है। इसे परमाणु मिसाइल बताकर और इसे लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला बताते से पूर्व उपराष्ट्रपति ने यह नहीं सोचा कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किए गए इस संशोधन को निरस्त कर दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए।

संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि संविधान के अनुसार किसी भी प्रकरण में ‘पूर्ण न्याय’ कर सके।

जब निर्णय सरकार की इच्छा अनुसार होता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती और सत्ताधारी दल के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा निष्पक्ष और न्याय प्रदान करने वाला बन जाता है। जब वही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सरकार को इच्छा के विपरीत देता है तो पूरी सरकार, उसका आई टी सेल, सत्ताधारी दल एवं उसके सभी नेता सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न विधेयों से विभुषित करने में जुट जाते हैं। भाजपा संसद निशिकांत दुवे ने तो यहां तक टवीट किया कि जब कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर यह आरोप तल लगा दिया कि वे देश को धार्मिक और गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं।

वक्क संशोधन कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके कुछ प्रावधानों पर क्रियान्वित रोकने के आदेश के बाद से भाजपा की टोल सेना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करने में जुट गई है। कोई इसे “शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया” बता रहा है तो कोई इसे ‘सुप्रीम कोटा’ तल कह रहा है।

अंत में यही कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ने जो शब्द सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कहे हैं वे उनके पद की मर्यादा के कतई अनुकूल नहीं हैं। उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने आज तक कभी ऐसा मर्यादा हीन बयान नहीं दिया है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ऐसे शब्द बोलता तो इसे उसकी नासमझी माना जा सकता था। धनखड़ न केवल एक ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान हैं अपितु वे एक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। उनके मुख से सर्वोच्च न्यायालय के प्रति ये शब्द अत्यंत महत्व रखते हैं। इसीलिए यह देश के लिए न केवल चिंतन का विषय है अपितु चिंता का भी, क्योंकि न्यायपालिका में विश्वास समाप्त होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र धूप्रापति
(पूर्व आई.एस. अधिकारी)

कहीं व्यवस्था में ही दोष तो नहीं चपरासी के लिए उच्च डिग्रीधारियों के आवेदन



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए उच्च डिग्रीधारियों के बहुतायत में आवेदन से हमारी संपूर्ण व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है। आखिर ऐसे हालात क्यों होते जा रहे हैं। कभी सफाई कर्मचारी के पद के लिए तो कभी चपरासी के पद के लिए उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं का आवेदन करना आम होता तल रहा है। कहने को तो इसके लिए किसी पर भी दोषारोपण आसान हो जाता है पर हालात सामने होने के साथ ही गंभीर चिंता के भी हो जाते हैं।

अब इसका शिक्षा व्यवस्था को ही

दोष दिया जाए या बढ़ती बेरोजगारी या फिर सरकारी नौकरी का मोह माना जाये कि राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में भर्ती के लिए मांगे गये आवेदन में 20 अप्रेल तक 23 लाख 65 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 53749 पदों के लिए आवेदन के लिए निर्धारित योग्यता दसवीं पास होना है वहीं दसवीं पास के पद के लिए आवेदन करने वालों में पीएच. डी,

ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं तकनीकी शिक्षा प्राप्त बीटेक और बीएड जैसी योग्यताधारी शामिल हैं।

इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस, आईपीएस, आरएएस, प्रोफेसर, शिक्षक या प्रदेशों की सिविल सर्विस व अन्य इसी तरह के उच्च पदों की योग्यता को पूरी करने वाले युवक रोजमर्रा की भाषा में कहें तो चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने में किसी तरह का संकोच नहीं कर रहे हैं। यह हालात हमारी संपूर्ण व्यवस्था को प्रश्नों के घेरों में खड़ा कर देती हैं। आखिर हमारी व्यवस्था का कहां रही है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त चयनित नहीं होते हैं तो सवाल यह उठेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी चपरासी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें। वहीं किसी कारण से शिक्षा पूरी नहीं कर सकने वाले युवक दसवीं की परीक्षा ही पास कर सके हैं और चपरासी के पद के लिए योग्य है तो उच्च शिक्षितों, अनुभवियों के सामने उनके लिए तो चयन की संभावना लगभग शून्य ही समझी जानी चाहिए।

यदि समान योग्यता वाले आवेदन इतनी बड़ी संख्या में होते तो एक अनार सी बीमार वाली बात तो हो जाती पर फिर सीधा—सीधा यही कहा जाता कि रोजगार के अवसर कम है पर उच्च अध्ययन प्राप्त युवाओं के चपरासी के पद के लिए आवेदन करना हमारी केवल शिक्षा व्यवस्था वृ ही नहीं अपितु पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पा रही।

इससे यह तो साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में ही दोष है। एक और तो सातवें वेतन आयोग के बाद से युवाओं में सरकारी नौकरी का मोह बढ़ा है। फिर रही –सही कसर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने पूरी कर दी है जब चुनावों में मुख्य मुद्दा रोजगार को लेकर उठाया जाता है। चुनावों में रोजगार या यों कहें कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होना चाहिए इससे नकारा नहीं जा सकता है पर केवल सरकारी नौकरी का ही चस्मा दिखाया जाता है तो परिणाम फिर इसी तरह के आते हैं। आजादी के बाद निजी क्षेत्र ने काफी विस्तार किया है।

एक समय ऐसा भी रहा है कि जब युवाओं का क्रेज निजी क्षेत्र के प्रति रहता था। निजी क्षेत्र में वेतन-भत्तों के साथ ही सुविधाओं का भी विस्तार था। ऐसा नहीं है कि आज ऐसा नहीं है। आज भी निजी क्षेत्र की अनेकों संस्थाओं में अच्छा पैकेज और सुविधाएं मिलती हैं। युवाओं को विदेश जाने तक के अवसर मिलते हैं। मेडीक्लेम व अन्य सुविधाएं भी आम हैं। हां परफॉर्मंस और टारगेट की बात अवश्य होती है।

सरकारी नौकरी के पीछे भागने का कारण एक तो सर्विस को लेकर किसी तरह का तनाव नहीं होना है। यों कहा जा सकता है कि सरकारी नौकरी में जांव सिक्योरिटी के साथ ही सुविधाओं का अंबार और पेंशन सुविधा के साथ ही जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में तो एक तरह का समझौता हो जाता है कि जो काम के प्रति निष्ठावान है उसे काम से लाद दिया जाता है और जो काम के प्रति अधिक गंभीर नहीं होते हैं।

उन्हें कहने को तो नाकारा कह दिया जाता है पर वास्तव में इतना कहने भर से उन्हें काम के बोझ की मुक्ति मिल जाती है। यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा एक बार सरकारी नौकरी में प्रवेश हो गया तो कोई कहने वाला तो होगा नहीं, यदि ज्यादा दिक्कत भी आती है तो कहीं से भी सिफारिश कराकर अपना काम चला ही लेंगे। एक बार नौकरी में प्रवेश होने के बाद ओवरएज होने तक प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया जा सकता है। इससे दो तरह की समस्या उत्पन्न होती है एक तो वास्तव में उस योग्यताधारी के सामने नौकरी की समस्या जस की तस रह जाती है जो उस पद की योग्यता ही पूरी कर पाता है, दूसरा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद नहीं मिलने के कारण सहायभूति में अन्य कार्य लिये लिया जाता है जिससे दोहरा नुकसान होता है।

एक तो उस पद के योग्य लोगों को नुकसान होता है तो दूसरा मूल पर का काम तो बाधित ही रहता है क्योंकि जिस पद पर चयन हुआ है वह काम तो करना ही नहीं है। अभी कुछ समय पुपनी ही बातें हैं और लगभग सभी जगह हालात यह हैं कि नगर निगमों में सफाई कर्मियों की भर्ती में अधिकांश चयनित उच्च शिक्षा प्राप्त होने या उच्च वर्ग से जुड़े होने के कारण चयनित होने के बाद उन्हें सफाई कर्मी का काम तो करना ही नहीं था और शिक्षा भी नहीं और उनकी सेवाएं ऑफिस में क्लर्कों के रूप में ली जाने लगी। इससे अधिकांश नगर निकायों की सफाई व्यवस्था तो प्रभावित हुई ही साथ ही असली दवेदार तो बेरोजगार ही रह

गए और रोजगार के नाम पर ऐसी भर्तियां हुईं जो बोझ बनकर ही रह गईं। यह वास्तविकता का एक पक्ष है दूसरा पक्ष तो उच्च योग्यता होने के बाद भी उसके अनुसार नौकरी नहीं मिलना है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए। सवाल यह उठता है कि बीटेक व्यक्ति को इंजीनियरिंग का काम नहीं मिलता है तो फिर उसकी पढ़ाई का मतलब ही क्या है। सवाल यह है कि जिस तरह से निजी क्षेत्र में नए-नए इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज खोले गये और उनमें शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया तो केवल डिग्री से क्या होने वाला है।

समस्या इतनी साधारण नहीं है जितनी इसे समझा जा रहा है। यह बढ़ती बेरोजगारी की समस्या नहीं है अपितु कहीं ना कहीं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का ही दोष है। हालात का समग्रता के साथ विश्लेषण करना होगा नहीं तो चपरासी हो या सफाई कर्मी इतने ही नहीं अपितु इनसे भी ज्यादा आवेदन आएं और भर्ती भी होगी, नौकरी पर भी आयेगे, वास्तविक युवाओं के लिए रोजगार समस्या ही बना रहेगा, सरकारी खर्चा तो यों ही होता रहेगा पर जिस उद्देश्य से या जिस काम के लिए पदों को भरा जाना है उसमें हालात नहीं बदलने वाले हैं। फिर यह कहना कि सफाई कर्मी है पर सफाई नहीं हो रही या चपरासी है पर चपरासी के काम करने वालों की कमी है तो हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। यह समूची व्यवस्था के सामने चुनौती है और इसका समाधान खोजना ही होगा।

—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
(वरिष्ठ लेखक)

घुमंतू जाति के बच्चों के लिये राज्य सरकार “चल विद्यालय” शुरु करेगी

घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब “चल विद्यालय” शुरू करेगी। दरअसल, घुमंतू जाति परिवारों का एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए रहे हैं। रोजगार के लिए घुमंतू परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। यही कारण है कि एक जगह पर स्थाई निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते और 2 से 3 साल स्कूल जाने के बाद ड्रॉपआउट की श्रेणी में आ जाते हैं।

हालात यह है कि हर साल राज्य में करीब 10 हजार विद्यार्थी अपनी

पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं। घुमंतू जाति के इन बच्चों को शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने “चल विद्यालय” खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवासी राजस्थानियों से इन विद्यालयों को खोलने में भागसााहों का रोल निभाने का आव्हान भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई द्वीर पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अब जल्द ही “चल विद्यालय” शुरू

- हालात यह है कि हर साल राज्य में करीब 10 हजार विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ रहे हैं
- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई द्वीर पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की

किए जाएंगे। इन “चल विद्यालय” के जरिए उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो घुमंतू जाति से हैं। इन विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर घुमंतू जाति के बच्चों को प्रवेश देकर उनके ही स्थान पर विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि वह शिक्षा से जुड़कर अपना भविष्य

में ऐसा ही एक प्रयोग वर्ष 1991 में “चरवाहा विद्यालय” के रूप में किया गया था।

यह विद्यालय गाय-भैंस चराने वाले बच्चों के लिए शुरू किए गए थे। छात्रों के मवेशी स्कूल के मैदान में चरने के लिए छोड़ने की व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन मवेशी चरवाहा विद्यालयों के मैदान में चरते थे तथा छात्र विद्यालय में पढ़ते थे। शिक्षक नेताओं ने बताया कि दो दशक पहले बीकानेर सहित राज्य के अनेक जिलों में घुमंतू जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए चल विद्यालय के तहत बस में कुछ शिक्षक संबंधित क्षेत्र में जाकर उन्हें पढ़ाई करवाते थे। बाद में योजना आगे नहीं बढ़ पाई।

महंगाई और गर्मी से हज जाने वाले यात्रियों में कमी आई

झुंझुनू, (निसं)। हज का मुकद्दस सफर एक मई से शुरू होगा, लेकिन करोना के बाद हज जाने वाले यात्रियों में लगातार गिरावट आ रही है। झुंझुनू ही नहीं, बल्कि राजस्थान और पूरे देश के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। वहीं सोमवार को झुंझुनू जिले से जाने वाले 37 हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया। मेडिकल जांच के बाद टीके लगाए गए और सभी को मुकद्दस सफर के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

झुंझुनू में पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया, जिन्हें किसी लांटरि का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। झुंझुनू जिले से 37 मुस्लिमों ने हज के लिए आवेदन किया, जिनका सभी का चयन हो गया। बताया जा रहा है कि हज का महंगा सफर और मक्का मदीना में इस वक्त पड़ने वाली तेज गर्मी के कारण अब हज के मुकद्दस सफर में जाने वाले मुस्लिमों की संख्या



झुंझुनू जिले से जाने वाले हज यात्रियों को कमरूद्दीन शाह दरगाह में प्रशिक्षण दिया गया।

कम हो गई है। यह संख्या करोना के बाद लगातार घट रही है। झुंझुनू के पिछले 10 सालों के आंकड़ों का बात करें तो करोना के बाद जब दुबारा सफर शुरू हुआ था, तब 36 हज यात्री गए थे। इस साल यह संख्या भी 37 के करीब है। पिछले साल जहां 72 हज

यात्री गए थे। वो अब कम होकर 37 तक पहुंच गई हैं। पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को हज पर जाने के लिए 5000 से अधिक सीटें दी गई थी, लेकिन 3420 ने ही आवेदन किया। करोना के बाद से हज पर जाने वाले लोगों के लिए लांटरि नहीं

- झुंझुनू से 10 साल में पहली बार 37 ही हज यात्री जाएंगे
- पिछले साल के मुकाबले लगभग आधे ही मुस्लिम लोगों ने हज जाने के लिए आवेदन किया

निकालनी पड़ी है। हज यात्रियों की संख्या में कमी आने के कारण महंगाई माना जा रहा है, जो सफर पहले 2 लाख रूपए तक हो जाता था। अब वह पांच लाख रूपए तक हो गया है। साथ ही उमरा वर्षभर चलता है, जो कम समय में हो जाता है। जबकि हज गर्मी के दिनों में होता है। इसकी इज्जत डेढ़ महीने तक रहना भी पड़ता है। इसके चलते भी अब हज जाने वालों में कमी आई है।

पैथर के हमले से तीन मवेशियों की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के लाखौला चौराहा रोड़ पर हुसनूद्दीन मेवाती के बाड़े में बंदे हुए चार गाय के बछड़ों पर पैथर ने हमला कर दिया। पैथर ने तीन गाय के बछड़ों को मौत के घाट उतार दिया। एक गाय के बछड़ा गंभीर घायल हो गया। वहीं वन विभाग व पशु चिकित्सालय की टीम ने मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया।

जानकारी के अनुसार बाड़े में चार गाय व उनके चार बछड़े बंधे हुए थे। परिवारजन रविवार की शाम को गायों का दूध निकालकर, घास डालकर अपने घर चले गए। सोमवार की सुबह गायों में कमी आने के कारण महंगाई माना जा रहा है, जो सफर पहले 2 लाख रूपए तक हो जाता था। अब वह पांच लाख रूपए तक हो गया है। साथ ही उमरा वर्षभर चलता है, जो कम समय में हो जाता है। जबकि हज गर्मी के दिनों में होता है। इसकी इज्जत डेढ़ महीने तक रहना भी पड़ता है। इसके चलते भी अब हज जाने वालों में कमी आई है।



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल

मंगलवार 22 अप्रैल, 2025

वैशाखा मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र दिन 12:44 तक, शुभ योग रात्रि 9:13 तक, तैत्तिल्य करण प्रातः 6:36 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 12:31 से

कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेघ, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज पंचम रात्रि 12:31 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:13 से 10:49 तक, लाभ अमृत 10:49 से 2:02 तक, शुभ 3:38 से 5:14 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:00, सूर्यास्त 6:50



मेघ

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृष

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



मिथुन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सांसने आ सकते हैं। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



धनु

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।



कर्क

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

मजदूर परिवार की मजबूरी, मां की बीमारी और बदकिस्मती के बावजूद सुजीत जीता

कोटा, (निसं)। मजबूरी हो या बदकिस्मती यदि मजबूत होसला है तो हर जंग जीती जा सकती है। कैरियर सिटी कोटा की कैयरिंग और मजबूत होसले का एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। कहानी बिहार के शेखपुरा निवासी छात्र सुजीत माधव की है।

सुजीत माधव ने जेईई-मेन 2025 क्रैक की है और जेईई-एडवांस्ड की तैयारी कर रहा है। सुजीत जेईई-मेन-2 में परीक्षा देने से चूक गया, क्योंकि परीक्षा केन्द्र तक साईकिल से गया था, साइकिल लॉक कर जा रहा था कि सामने ही गेट बंद हो गए और सुजीत बाहर ही रह गया। अब जेईई-मेन-1 के रिजल्ट 98.555 पर्सेंटेटिड स्कोर के आधार पर जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई किया है। यही नहीं सुजीत अपनी मां की बीमारी को लेकर भी पिछले दो साल से परेशान है, लेकिन हार नहीं मानी। सुजीत को एलन कोटा ने दोनो वर्ष शुल्क में विशेष रियायत भी दी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुजीत ने जेईई-मेन 2०25 में एआईआर-22268 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 5625 प्राप्त की है।

मां को पहले ब्रेन हेमरेज फिर कैसर-बिहार के शेखपुरा निवासी सुजीत ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। परिवार को रोज खाने के लिए रोज

कमाया पड़ता है। पिता चुनचुन कुमार खेती करते हैं और मां किरण देवी गृहिणी है। खेती से घर का अनाज जितना हो पाता है, बाकि समय मजदूरी या छोटे-मोटे काम घर परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। घर भी आधा कच्चा आधा पक्का बना हुआ है। सुजीत पढ़ाई में होशियार था, इसलिए वर्ष 2०23 में कोटा आया और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। पिता ने गांव में साहूकारों से ब्याज पर पैसा उधार लेकर सुजीत को पढ़ने भेजा। सुजीत यहां अच्छा प्रदर्शन कर रहा था लेकिन 8 नवंबर 2023 को मां को ब्रेन हेमरेज हो गया। मां से लगवाव होने के कारण सुजीत काफी परेशान हुआ। कुछ दिनों के लिए घर गया लेकिन 12वीं की परीक्षा देनी थी इसलिए भाई के समझाने पर वापिस कोटा आ गया। यहां फैकल्टीज ने मोटिवेट किया और उसने 12वीं कक्षा 81 प्रतिशत अंकों से पास की। सुजीत ने 1०वीं कक्षा 85 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। पिछले साल मां को कैसर ने घेर लिया, मां का इलाज एम्स पटना में चल रहा है।

सुजीत ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और कोटा में पढ़ाई करना सपने के जैसा था लेकिन हिम्मत कर के जैसै-तैसै कोटा आया। कोटा के लोग काफी अच्छे और सपोर्टिव हैं। मैं पिछले दो साल से



सुजीत

तलवंडी में जिस पीजी में रह रहा हूं, उसका मुश्किल से दो या तीन बार किरिया दिया है। पीजी की संचालिका ने बोला हुआ है कि आप पढ़ाई करों, किराय की टेंशन मत लो, जिस दिन इंजीनियर बन जाओं तो मुझे बता देना। मैंने लिख अहं! किया। है। इसी तरह फीस भरने के पैसे नहीं थे तो एलन ने 7० पर्सेंट तक फीस में रियायत दे दी। दो तीन साल से इसी तरह फीस दे रहा हूं।

कोटा ने ऐसे बदली जिंदगी, घर से भागकर आया था सबसे बड़ा भाई-मजदूर परिवार के तीन बेटों के इंजीनियर बनने की कहानी वर्ष 2०16 में शुरू हुई थी। जब सबसे बड़ा बेटा रजनीश इंजीनियर बनने का सपना लेकर बिना बताए कोटा आया था। रजनीश ने बताया कि परिवार की स्थिति कोटा भेजने की

■ **कोटा केयर्स-बिहार शेखपुरा के मजदूर परिवार के सुजीत की कोटा ने बदली जिंदगी**

■ **मजबूरी-फीस के पैसे नहीं थे, कोचिंग में दी रियायत, पीजी ने नहीं मांगा किराया**

नहीं थी इसलिए पापा ने साफ मना कर दिया था। मुझे कोटा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन ये पता था कि कोटा-पटना ट्रेन कोटा जाती है। इसलिए जेब में पांच सौ रूपए लेकर घर से भागकर कोटा आ गया। मुझे याद नहीं लेकिन, मैंने शायद ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीदा था। बस रिस्क लेकर ट्रेन में बैठ गया। यहां आने के बाद लोगों से पूछा और एलन की समन्वय बिल्डिंग आ गया। यहां मुझे संतोष सर और आरके खंगार सर मिले। मैंने इनको स्थिति समझाई।

उन्होंने एक हॉस्टल में रखवा दिया। हॉस्टल संचालक ने भी किराया नहीं मांगा। कोचिंग में भी दो महीने तक ऐसे ही पढ़ाई की इसके बाद दादाजी ने पैसों की व्यवस्था की। इसके बाद वर्ष 2०19 में रजनीश अपने सबसे छोटे भाई सुजीत

को लेकर भी कोटा आ गया। उस समय सुजीत 9वीं कक्षा में था। कोटा में रहने के दौरान रजनीश ने बीच वाले भाई मृत्युंजय को गाईड किया और उसे स्टडी मंटेरियल भी भेजा, जिससे मृत्युंजय ने पढ़ाई की। वर्ष 202० में रजनीश ने जेईई मेन दिया और एडवांस के लिए क्वालीफाई किया लेकिन रैंक पीछे आने के कारण उसे कॉलेज नहीं मिला। ऐसे में जेईई मेन के आधार पर नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले लिया। इसके बाद वर्ष 2०22 में मृत्युंजय ने भी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन लिया।

सुजीत के बड़े भाई रजनीश कुमार ने बताया कि हम तीन भाई और एक बहिन हैं। सबसे बड़ा मैं हूं और मैं पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था। मां की बीमारी की वजह से मुझे बीटेक बीच में छोड़नी पड़ी लेकिन सुजीत और बीच वाले भाई को पढ़ा रहा हूं। सुजीत घर पर रहता था तो सास काटने जाता था, गाएं चराने जाता था और घर के अन्य कामों में व्यस्त रहता था लेकिन पढ़ाई में होशियार था। जब ये 8वर्ष में था तो 1०वीं क्लास की ट्रिगगेमेट्री सॉल्व कर देता था। इनको देखते हुए ही मैंने पापा से बात की और भाई मुश्किल से सुजीत को कोटा भेजने के लिए तैयार किया।

सार-समाचार

बिरला को समस्याओं से अवगत कराया

कोटा, (निसं)। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान, कोटा के जिलाध्यक्ष तेजराज सिंह के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने ओम कृष्ण बिरला अध्यक्ष लोकसभा से उनके कोटा आगमन के दौरान सेंट की और पेंशनर्स की कुछ समस्याओं के संबंध में उनको अवगत कराया। उन्होंने सेवारत पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार द्वारा मां में मेस तथा वर्दी भत्ता बढ़ाने और सेमी डिलक्स बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही कोटा रेंज में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप-निरीक्षक की विभागीय परीक्षाएं आयोजित करने व बीपीसी के माध्यम से पदोन्नति प्रदान करने पर भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त कोटा के विकास को गति देने की दिशा में एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी सराहना की और संगठन द्वारा हर रचनात्मक कार्य में सहयोग हेतु आभारस्त किया। प्रतिनिधि मंडल में घनश्याम शर्मा, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जगदीश प्रभाव मीणा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भंवर सिंह हाडा, उपाध्यक्ष, विजय सिंह कुंतल, कार्यालय मंत्री, राम दयाल नगर तथा हरिराज सिंह, प्रचार मंत्री, नंदलाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष तथा सत्यापन सिंह, कार्यकारिणी सदस्य आदि भी उपस्थित रहे।

सूने पड़े मकान में चोरी का मामला दर्ज

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर थाना इलाके में एक सूने पड़े मकान में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता महिला इन्द्रा की रिपोर्ट पर मामला ला कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में सामने आया कि महिला अपने पति के साथ दो घंटे के लिये किसी रिस्तेदार के यहां गईं और जब वह वापस लौटी और मकान के बाहर लगे ताले को खोलकर दृष्टि ने अंदर जाकर देखा तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। घर से जेवर व अन्य सामान चोरी हो गया था। जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्षमण गुर्जर ने बताया कि इन्द्रा ने रिपोर्ट दी है कि वह किराये के मकान में रहती है मकान में ब्यूटी पालर भी खोल रखा है। रिपोर्ट में कहा कि रिविगर शाम को पति के साथ किसी रिस्तेदार के यहां गये थे और शाम को वापस लौटी। रिपोर्ट में कहा कि लॉक खोलकर अंदर गये तो देखा रूम का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। थानाधिकारी ने बताया कि महिला ने मंगलसूत्र व अन्य सामान चोरी की रिपोर्ट दी है। महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

कोटा, (निसं)। दिगम्बर जैन समाज के प्रतिष्ठित संगठन श्रदिगम्बर जैन सोशल पुष फेडरेशन कोटा रीजन्स की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को बघेरवाल मांगलिक भवन, झालावाड़ रोड पर गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष अनिल ठोरा, सचिव पीयूष जैन सहित 43 सदस्यीय न्याय कार्यकारिणी ने पद की शपथ ली और विधिवत रूप से कार्यभार संभाला। समारोह के मुख्य अतिथि, फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेन्द्र कांसल ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा, 'कोटा रीजन हमेशा नवाचार, समर्पण और नेतृत्व के लिए जाना जाता रहा है।' उन्होंने नई कार्यकारिणी को सामाजिक सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दीं और पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया। उन्होंने कोटा रीजन से मोक्षरथ की मांग की।

12429 घरों का सर्वे किया

कोटा, (निसं)। कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना है' अभियान एवं मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के तहत सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की 794 टीमें ने जिले में 12429 घरों का सर्वे कर लार्वारोधी व जागरूकता गतिविधियां की। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि मौसमी बीमारियां डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम संबंधी गतिविधियां जारी है। टीमों ने 18173 कंटेनरों जिनमें टंकी, कुलर, गिरिण्डे आदि अन्य की जांच की, इस दौरान लार्वा पाए 52 कंटेनरों को उपचारित किया, 1०74 कंटेनरों को खाली कराया, 465 कंटेनरों में टेमोफास व 3०2 स्थानों पर एम्पलैओ डाला। इस दौरान 1८7 ब्लड स्लाइड भी ली गईं। 268 कमरों में पायरेथ्रम का स्प्रे किया गया। आमजन को बचाव-रोकथाम संबंधी जागरूकता के पम्फलेट वितरित किए, पोस्टर व स्टicker चस्पा किए।

दिया कुमारी का स्वागत किया

कोटा, (निसं)। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि कोटा प्रवास पर प्यारी दिया कुमारी उपमुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का नयापुरा चौराहा पर भाजपा शहर जिला कोटा द्वारा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में 51 किलो पुष्पहार से भव्य स्वागत करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री के साथ वित्त और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में हाड़ौती को अनेकों सौगातों देते हुए सड़कों का जाल बिछाने का तोहफा दिया है जिसके लिए एक कोटा की भरती पर दिया कुमारी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मशीनों के माध्यम से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि दिया कुमारी ने महिलाओं की चिंता करते हुए महिलाओं को लगातार संबल देने का प्रयास किया है।

विद्यालय में दरी पट्टियां व फर्श भेंट

रामगंजमण्डी, (निसं)। राजकीय उच्च प्रथम विद्यालय रैतिया चौकी में सोमवार को भारत विकास परिषद महावीर शाखा कोटा द्वारा 2०0 विद्यार्थियों के बैठने के हेतु सूती की दरी पट्टियां एवं फर्श भेंट किए गए। इस अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शुभारंभ में संस्था के सुरेन्द्र मोहन शर्मा, महावीर शाखा संरक्षक देवकीनंदन गुप्ता सचिव, राकेश दीक्षित सेवा प्रकल्प प्रशासी, देवाशीष मुखर्जी द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

आमजन के

लिए प्याऊ लगाई

कोटा, (निसं)। कोटा में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, हीट वेव के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं, आमजन को शीतल पेय उपलब्ध कराए जाने और राहत प्रदान करने के लिए जगह-जगह शीतल जल और शरबत के काउंटर लगाए जा रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से टीम पंकज मेहता द्वारा सोमवार को रामपुरा कोतवाली थाने के सामने शीतल जल के लिए प्याऊ लगाई गई। प्याऊ का शुभारंभ राजस्थान रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष, कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कुंज बिरला एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता द्वारा किया गया। टीम पंकज मेहता के ललित चित्तीड़ा ने बताया कि इस अवसर पर छाछ व लस्सी का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर प्रतिदिन कैपूर का ठंडा पानी आमजन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

महावीर स्वामी का 5० वर्षों बाद महामस्ताभिषेक हुआ

छबड़ा (निसं)। दिगम्बर जैन मंदिर पर स्वर्णिम पलों के तहत आचार्य विद्यासागर एवं समर्थ सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य 1०8 मुनि सुव्रत सागर महाराज के सानिध्य में समाज के सोभाग्य से मन्दिर पर वर्तमान शासन नायक एवं मूलनायक भगवान महावीर स्वामी का महामस्ताभिषेक, 1०8 कलशों से कलशाभिषेक एवं शांति धारा की गई। इस अवसर पर भामण्डल लगाये गये। इस पुण्य अवसर पर छबड़ा जैन समाज के अलावा छीपाबडौद एवं मध्यप्रदेश सहित अन्य जगहों के समाज के लोगों ने भी धर्म लाभ उठाया।

स्थानीय दिगम्बर जैन मंदिर पर रविवार को मुनि सुव्रत सागर महाराज के परम सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। छबड़ा आए मुनि सुव्रत सागर महाराज के सानिध्य में सुबह

लगभग 5० वर्षों बाद जैन धर्म के वर्तमान शासन नायक एवं मूल नायक भगवान महावीर स्वामी का महामस्ताभिषेक तथा 1०8 कलशों से कलशाभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान की शान्ती धारा की गई। महामस्ताभिषेक करने का सोभाग्य प्रकाशचन्द्र, जितेंद्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार लुहाडिया एवं प्रवीण कुमार अभिनव कुमार पाण्डेया ने 45-45 हजार रुपये की बोली लगाकर या। साथ ही शांतिधारा करने का शोभाग्य दीपचंद, आशा लुहाडिया एवं प्रवीण कुमार अभिनव पर चन्द्र प्रकाश शिखरचन्द, निमल कुमार, प्रमोद एवं वन्दन चन्द लुहाडिया ने वेदी जी में चांदी की प्रतिमा विराजमान कराने के लिये 6 किलो चांदी देने की घोषणा की साथ ही राकेश कुमार

अवि कुमार द्वारा अपने पिता स्वर्गीय महावीर लुहाडिया की पुण्य स्मृति में वेदि जी में अष्ट प्रतिहार एवं चांदी की पेटी चढ़ाई गई साथ ही दीपचंद आशा लुहाडिया ने विधान में प्रतिमा जी विराजमान करने के लिये चांदी का सिंघासन दिया।

मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान पार्वन्या भगवान एवं नेमीनाथ भगवान के चांदी के भामण्डल भी लगाये गए। मूल नायक महावीर स्वामी का चांदी का भामण्डल छबड़ा निवासी रामस्वरूप धर्मपत्नी मोना गोयल एवं बारां निवासी रामदयाल भीमो गोयल द्वारा तथा किलो चांदी का भामण्डल संजीव कुमार जैन डिस्क वाले, प्रकाश चन्द रामपुरिया, प्रवीण कुमार अभिनव कुमार पाण्डेया, निमल कुमार लुहाडिया द्वारा उड़ाये गए।

प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को मजबूत करेगी डबल इंजन की सरकार : दिया कुमारी

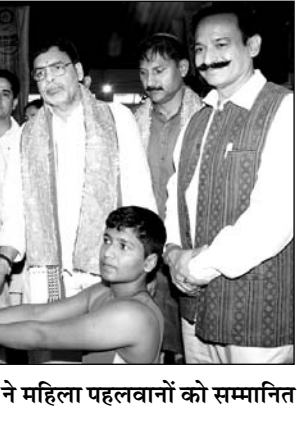
कोटा, (निसं)। प्रदेश की उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कोटा में चल रही अंडर-2० राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर से आई महिला खिलाड़ियों को सम्मान किया तथा पदक विजेताओं को मंडल भेंट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने का काम कर रही है। खेल के इम्फोर्स्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं में सुधार हो रहा है। अब राजस्थान भी खेलों में सिरफ़ी बनेगा और यहां को पदक विजेताओं की सूची में महिलाएं अग्रणी रहेंगी। उन्होंने कोटा में हो रही अंडर-2० राष्ट्रीय कुश्ती



कोटा में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला पहलवानों को सम्मानित किया है।

प्रतियोगिता को भी प्रदेश में कुशियों को बढ़ावा देने की दिशा में मौल का पथर साबित होगी। इससे प्रदेश में कुशियों के प्रति रूचि बढ़ेगी और कुश्ती के खिलाड़ियों के स्तर में भी इजाफा होगा।

आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए उन्होंने राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता की सराहना भी की। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि



कुश्ती का खेल हमारी संस्कृति और परंपराओं में गहरा-बसा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने यहां आकर देशभर का आर खिलाड़ियों विशेष तौर पर महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है वह निश्चित तौर पर उन्हें आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने दिशा में गतिमान करेगा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कोटा में आयोजित हो रही कुश्ती प्रतियोगिता ने खिलाड़ियों

रिफ्रेशमेंट कैंटीन का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे का कोटा रेल मंडल डीआरएम अनिल कालरा के मार्गदर्शन में यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के साथ-साथ मंडल में कार्यरत कर्मचरियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के परिसर में गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) के तहत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के नेतृत्व में "रिफ्रेशमेंट कैंटीन" का संविदा के माध्यम से आवंटन किया गया। रिफ्रेशमेंट कैंटीन का उद्घाटन डीआरएम अनिल कालरा द्वारा रिवन काउंटर शुभारंभ किया गया। पूर्व में मंडल कार्यालय में संचालित हो रही कैन्टीन बंद होने से कर्मचारी एवं आगन्तुकों के लिए रिफ्रेशमेंट का आभाव था। मंडल कार्यालय में शुभारंभ किये गये "रिफ्रेशमेंट कैंटीन" में कर्मचारी एवं आगन्तुकों के लिए अलमलारा, खानपान उचित दर के अतिरिक्त गेम जोन (कैरम एवं चेस) की भी सुविधा मिलेगी। इस कैन्टीन का शुभारंभ कार्य संविदा के माध्यम तीन वर्ष की अवधि हेतु आवंटित किया गया है। यह सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने की दिशा में मंडल द्वारा किया गया सरव्तीय पहल है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ललित कुमार धुरंधर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुप्रकाश, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक विनोद मीना, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ सुमना पटनायक एवं अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

लव-कुश छात्रावास परिसर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण

सहयोग प्राप्त हुआ। कुशवाहा क्षत्रीय विकास समिति कोटा संभारा के अध्यक्ष रमेश चंद कुशवाहा एडवोकेट विधिक सलाहकार, चंद्रमोहन कुशवाहा एडवोकेट, संस्था के सचिव भरत सिंह कुशवाहा एडवोकेट, नरेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट, दुर्गा शंकर कुशवाहा एडवोकेट, कुशावहा एडवोकेट, चंद्रप्रकाश कुशवाहा, राम रतन कुशवाहा कंपाउडर आदि उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी का वांछित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बूदादीत थाना पुलिस टीम ने गिल्ट के बने आभूषणों को चांदी का बताकर गिरवी रखकर धोखाधड़ी कर रूपये ऐंठने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ हेतु ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निदेशन में विशेष अभियान चला रखा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि बूदादीत थाने के उपनिरीक्षक धानाधिकारी रघुवीर सिंह के नेतृत्व में गटिंट टीम ने कार्यवाही करते हुए गिल्ट के बने आभूषणों को चांदी का बताकर गिरवी रखकर धोखाधड़ी कर रूपये ऐंठने के मामले में वांछित आरोपी तलाब गांव अनंतपुरा निवासी गोरानाथ (59) को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी हैं, वहीं मामले में वांछित चल रहे आरोपी गोरानाथ को भी गिरफ्तार कर लिया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			
क्रमांक:-एफ-15/क.भू.क/2०25/1115	विवरणित	दिनांक:-21.4.2०25	
सर्वे साधारण को जर्बे विज्ञापित सूचित किया जाता है कि ग्राम बालाकुण्ड में स्थित कृषि भूमि योजना न्यू जवाहर नगर खसरा नं. 41/268 में स्थित भूखण्ड संख्या डी-26 क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज आवेदक श्री महेश कुमार चौरसिया पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल चौरसिया निवासी 17/235, नन्द किशोर जी का बघोला, बुजराजपुरा कोटा राज. नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। डेक भूखण्ड का पट्टा आवेश क्रमांक 2526 दिनांक ०4.०8.2००3 को मोहन कुमार यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान रजि. विक्रय पत्र दिनांक ०5.०3.2०05 को जर्बे मुख्तारआम अनिल अखवाल पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा प्रिया शर्मा पॉल श्री राजेन्द्र शर्मा के पक्ष में किया गया। क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्बे रजि. विक्रय पत्र दिनांक 25.1०.2०12 से आवेदक के पक्ष में किया गया है।			
अतः श्री महेश कुमार चौरसिया पुत्र स्व. श्री ग्यारसी लाल चौरसिया के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किया जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अग्रोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करी मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।			
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपांतरण नगर परिषद बारां			
क्रमांक:-नया.क/पा./2025/486-87	लोक सूचना	दिनांक:-21.4.2०25	
सुरेंद्र गोयल पुत्र श्री द्वाराकालाल जति महाजन निवासी कलमण्डा तह. व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय प्रयोजन) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिप्राय अथवा निर्णय के निर्वाण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात जिले सहित तहसील का नाम			
बारां, तहसील व जिला बारां	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
	गोपालपुरा	16०/749	०.85 है.
		822/158	०.28 है.
		16०/75०	०.80 है.
	कुल किता 3		में से ०.6800 है.
			कुल कृता 1.81 है।

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वीक प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने और अपभूति अधिकारों के निर्वाण पर कोई आवेदन है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भूतरी किसी कार्य दिवस पर कोटा विकास प्राधिकरण सम्य के दौरान अग्रोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आवेश प्रस्तुत कर सकेंगा।
उपयुक्त नियम सार के भीतर-भीतर किसी आवेश के अभाव में यह समझा जायेगा कि, तथा पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री नीरज सचदेव पुत्र स्व. श्री बरत सचदेव द्वारा उक्त भूखंड संख्या 235 इंडियनसेट सेक्टर व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।
अतः जरुरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञाित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 235 योजना इंडियनसेट सेक्टर व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण श्री नीरज सचदेव पुत्र स्व. श्री बरत सचदेव के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			
क्रमांक:-एफ11/ विकर/2०25/1532	दिनांक:-21.०4.2०25		

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना इंडियनसेट सेक्टर व्यावसायिक भूखंड संख्या 236 का नामहस्तान्तरण पत्र क्रमांक 3९8-99 दिनांक 12.12.2०14 को श्री बरत सचदेव पुत्र श्री भीष्मराज सचदेव के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री बरत सचदेव पुत्र श्री भीष्मराज सचदेव की मृत्यु दिनांक 13.11.2०24 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत श्री बरत सचदेव पुत्र श्री भीष्मराज सचदेव के विधिक वारिसता द्वारा मृत्यु रजिस्टर्ड रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, राशय पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्री नीरज सचदेव पुत्र स्व. श्री बरत सचदेव द्वारा उक्त भूखंड संख्या 236 इंडियनसेट सेक्टर व्यावसायिक अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।
अतः जरुरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञाित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 236 योजना इंडियनसेट सेक्टर व्यावसायिक का नामहस्तान्तरण श्री नीरज सचदेव पुत्र स्व. श्री बरत सचदेव के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा			
क्रमांक:-एफ11/ विकर/2०25/1274	दिनांक:-21.4.२०25		

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना
कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवेदन भूखंड संख्या-1०4 डी होलसेल न्यू क्लाय मॉडर्न व्यावसायिक योजना कोटा का आवंटन लोहा के पत्र क्रमांक 1663 दिनांक 28.12.1996 द्वारा श्री चंदप्रसा हेमन्त कुमार लोहा प्रो. कमल लोहा को आवंटित किया गया था। विस्मयी लोहा दिनांक 31.०3.1999 को हो चुकी है। श्री कमल कुमार लोहा पुत्र श्री हुकुम चन्द लोहा के द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्बे रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.०9.2००4 को श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री श्याम लाल पुरसवानी के पक्ष में कर दिया गया है। श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री श्याम लाल की मृत्यु दिनांक 22.11.2००4 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात पुष्पादेवी के विधिक वारिसता के द्वारा श्री श्याम लाल पुत्र श्री हरीराम के पक्ष में पुष्पादेवी के हक का त्याग किया गया है। हकत्याग प्रतिलि श्री श्याम लाल पुत्र श्री हरीराम एवं सह पट्टीनर कमल कुमार लोहा पुत्र श्री हुकुम चन्द लोहा के द्वारा संयुक्त नाम से नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। अतः जरुरी आम सूचित किया जाता है।
अतः जरुरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञाित जारी होने के 7 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवाम/भूखंड संख्या 1०4 डी होलसेल न्यू क्लाय मॉडर्न व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्री श्याम लाल पुत्र श्री हरीराम एवं सह पट्टीनर कमल कुमार लोहा पुत्र श्री हुकुम चन्द लोहा नाम से जारी कर दी जावेगी।
उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

जाहिर आम सूचना दिनांक - 21.4.25

क्रमांक 136 आवास संख्या 2-ख-8 केरावपुरा कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर

श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया गया था। अब आवास का पर्याप्त श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर श्री

लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया गया है। 23.02.1991 को अपने पत्र में कहा गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के

आधार पर श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा का मृत्यु दिनांक 05.10.2024 को एवं

इसकी पत्नी श्रीमती सुषमा बाई को मृत्यु दिनांक 09.09.2022 को हो चुकी है। श्री लक्ष्मीनारायण

राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा एवं आवास को वसीयत अपने जीवनकाल में अर्जित वसीयत नाम

लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया गया है। 04.10.2024 को श्री अंजित कुमार पुर श्री केतरी लाल कोटा का

मृत्यु दिनांक 23.02.1991 को अपने पत्र में कहा गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री

लक्ष्मण प्रसाद कोटा का मृत्यु दिनांक 05.10.2024 को एवं इसकी पत्नी श्रीमती सुषमा बाई को

मृत्यु दिनांक 09.09.2022 को हो चुकी है। श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा

एवं आवास को वसीयत अपने जीवनकाल में अर्जित वसीयत नाम लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया

गया है। 04.10.2024 को श्री अंजित कुमार पुर श्री केतरी लाल कोटा का मृत्यु दिनांक 23.02.1991 को

अपने पत्र में कहा गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा का मृत्यु

दिनांक 05.10.2024 को एवं इसकी पत्नी श्रीमती सुषमा बाई को मृत्यु दिनांक 09.09.2022 को हो

चुकी है। श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा एवं आवास को वसीयत अपने

जीवनकाल में अर्जित वसीयत नाम लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया गया है। 04.10.2024 को

श्री अंजित कुमार पुर श्री केतरी लाल कोटा का मृत्यु दिनांक 23.02.1991 को अपने पत्र में कहा

गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा का मृत्यु दिनांक 05.10.2024 को

एवं इसकी पत्नी श्रीमती सुषमा बाई को मृत्यु दिनांक 09.09.2022 को हो चुकी है। श्री लक्ष्मीनारायण

राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा एवं आवास को वसीयत अपने जीवनकाल में अर्जित वसीयत

नाम लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया गया है। 04.10.2024 को श्री अंजित कुमार पुर श्री केतरी लाल

कोटा का मृत्यु दिनांक 23.02.1991 को अपने पत्र में कहा गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा का मृत्यु दिनांक 05.10.2024 को एवं इसकी पत्नी श्रीमती सुषमा बाई को

मृत्यु दिनांक 09.09.2022 को हो चुकी है। श्री लक्ष्मीनारायण राजगो पुर श्री लक्ष्मण प्रसाद कोटा

एवं आवास को वसीयत अपने जीवनकाल में अर्जित वसीयत नाम लक्ष्मण प्रसाद कोटा का किया

गया है। 04.10.2024 को श्री अंजित कुमार पुर श्री केतरी लाल कोटा का मृत्यु दिनांक 23.02.1991 को

लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे की मजबूती में पब्लिक सर्वेंट की भूमिका अहम : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे की मजबूत बनाए रखने में पब्लिक सर्वेंट की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत व विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की योजनाओं से लाभान्वित करना बेहद जरूरी है एवं इस कार्य के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लोक सेवकों की है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट को सुशासन के लिए कर्तव्यनिष्ठा, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। शर्मा सोमवार को झालाना इंग्री स्थित हरिशचन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में पब्लिक सर्वेंट दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति अभाव में जब पब्लिक सर्वेंट के पास आता है, तो पूर्ण जिम्मेदारी से उसकी हरसंभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए पब्लिक सर्वेंट को निरंतर जनसुनवाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हमें टीम भावना के रूप में सार्वजनिक हित और लोक-कल्याण के साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सदाश वल्लभभाई पटेल ने वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में पब्लिक सर्वेंट को ‘स्टील प्रेम’ अर्थात् देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ कहा था। उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्वेंट का अर्थ निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए कार्य



हरिशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान मे आयोजित पब्लिक सर्वेंट दिवस 2025 के अवसर पर सोमवार को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सम्मान पुरस्कार के तहत आयुक्त कृषि सुश्री चिन्मयी गोपाल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। आयुक्त कृषि को यह सम्मान वर्ष 2024 में राज्य सरकार के संपर्क पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों को ईमानदारी, समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से निस्तारण करने के उपलक्ष्य में दिया गया है।

करना है। बिना किसी स्वार्थ के, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची पब्लिक सर्वेंट होती है। इसलिए पब्लिक सर्वेंट दिवस मनाने का उद्देश्य पब्लिक सर्वेंट के योगदान को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकहित, त्वरित एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संकल्पना हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सेवाओं की सरल, सुगम एवं त्वरित प्रदायगी के लिए नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक जिला-एक उत्पाद नीति, नई पर्यटन इकाई नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीन खनिज नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियां जारी की गई हैं। साथ ही, ग्राम स्तर तक ई-फाइल प्रणाली को लागू कर दिया गया है तथा सभी विभागों में ऑन-लाइन पेपर लेस कार्य हो रहा है।

शर्मा ने कहा कि आमजन के कार्यों के निस्तारण में तेजी आई है। जन

अभियोगों का निराकरण सुशासन का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से डेढ़ करोड़ से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। गत एक साल में दर्ज लगभग 33 लाख मामलों में से 99 प्रतिशत से अधिक निस्तारित हो चुके हैं तथा दिसंबर माह में मनाये गये सुशासन सप्ताह में भी राजस्थान का स्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस

- ‘हमारा प्रयास राजस्थान की तत्वीर और तकदीर को बदलना’
- मुख्यमंत्री ने की कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत
- पब्लिक सर्वेंट को मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार

दौरान प्रदेश में सुशासन के तहत किए गए नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, संपर्क पोर्टल पर लोक शिकायतों के निस्तारण की विभाग/व्यक्तिगत/जिला श्रेणी में विभिन्न अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2025 एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किए। इससे पूर्व शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह की शुरुआत की। साथ ही, उन्होंने एच.सी.एम. रीपा परिसर में फोटो गैलरी एवं सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के मॉडल का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अजीतजी बनर्जी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं सभी जिलों से लोक सेवक वीसी के माध्यम से जुड़े।

‘शिक्षा व्यवसाय नहीं है, पवित्र कार्य है’

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित एक समारोह में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और शिक्षण संस्थाओं का सम्मान और अभिनंदन किया।

बागडे ने इस दौरान भारत के प्राचीन तक्षिशाला, नालंदा, विक्रम विश्वविद्यालय आदि की चर्चा करते हुए कहा कि शैक्षिक क्षेत्र में आरम्भ से ही भारत विश्व भर में अग्रणी रहा है।



अमेरिकी उपराष्ट्रपति बेंस की आमेर विजिट के दौरान उनका स्वागत हथिनी पुष्पा व चंपा करेगी। इसके लिए उन दोनों को हाथी गाँव में तैयार किया जा रहा है।

संत धन्ना भगत ने मानव कल्याण के लिए किया कार्य : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि धन्ना भगत का संत परंपरा में विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाते हुए मानव-मात्र की सेवा की तथा कर्म पर उसी तरह जोर दिया, जैसे भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता में अपने संदेश में दिया है। शर्मा ने कहा कि धन्ना भगत जी ने जाल-पात का विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया।

शर्मा सोमवार को जयपुर जिले के फागी में संत धन्ना भगत की जन्म स्थली नोखा-नाड़ी में उनके जयन्ती महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संत धन्ना भगत जी ने मानव कल्याण के लिए जो शिक्षाएं दी हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। धन्ना भगत जी ऐसे संत हैं, जिनके प्रति हिंदुओं के साथ-साथ हमारे सिख भाई-बहन भी श्रद्धा रखते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में सनातन का स्वर्णकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए/जितना काम हुआ है, उसना पहले कभी नहीं हुआ। पिछले साल ही प्रधानमंत्री के कर कमलों से अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा

- ‘उनकी रचनाओं से समाज में व्याप्त बुराइयां हुई दूर’
- ‘हमारी सरकार कर्वाएगी 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग, 50 हजार को एसी ट्रेन से तीर्थयात्रा’

हुई और 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम वैभव निखरा और उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ। साथ ही, सोमनाथ का विकास हुआ और केदार घाटी का पुनर्निर्माण हुआ।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम अगले वर्ष 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से यात्रा कराएंगे। इसके अतिरिक्त 50 हजार वरिष्ठजनों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों

के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये तथा देवस्थान विभाग के अधीन राज्य के बाहर स्थित मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। राज्य सरकार ने मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह भी किया है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा की संत धन्ना भात समाज में समानता, सरलता और सच्ची आस्था के प्रतीक थे। उन्होंने गौ सेवा को भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने धन्ना भगत मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेश की सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, अध्यक्ष धन्ना भगत समिति नारायण डूडी सहित जनप्रतिनिधि, साधु-संत एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नेशनल हेराल्ड मामले का सच सामने लाएगी कांग्रेस : कन्हैया कुमार

जयपुर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस 25 अप्रैल को होने वाली सुनवाई से पहले पूरे देश में आंदोलन के जरिए यह बताएगी कि इस कार्रवाई से मोदी सरकार और वाले चुनावों में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है।

इसी सिलसिले में सोमवार को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपना पक्ष रखा। जयपुर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है जो चुनाव के साथ भी और उसके बाद भी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करने की बात करते हैं, वो बात ईडी के संदर्भ में कही जाती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी की ध्यान भटकआओ योजना के तहत ईडी काम कर रही है। भाजपा ने राजनीतिक लड़ाई लड़ने वालों को ईडी के जरिए दो विकल्प दिए हैं, या तो बीजेपी में आ जाओ या फिर जेल जाओ, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे डरते नहीं हैं।

कांग्रेस चलाएगी 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान प्रारम्भ करेगी। कांग्रेस 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में चलाएगी, क्योंकि देशभर में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रदेश में संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 24 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर

- 28 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे का आना प्रस्तावित

अभियान की सफलता हेतु जिम्मेदारी पदाधिकारियों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे द्वारा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करने एवं प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों व मण्डल एवं ब्लॉक तथा जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ संवाद का भी

कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि 3 मई से 10 मई तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैलियां आयोजित होंगी। उसके पश्चात् 11 से 17 मई तक विधानसभा क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता के वादे के साथ जो विश्वासघात भाजपा ने किया है तथा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है।

इंश्योरेंस क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा अवधि में बीमित वाहन चोरी होने पर उसका क्लेम नहीं देना पर बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 2.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने 2.50 की बीमा राशि का भुगतान भी ब्यज सहित करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश हनुमान प्रसाद के परिवार पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवार में कहा गया कि उसने अपनी कार का विपक्षी बीमा कंपनी से 14 जुलाई, 2016 से 13 जुलाई, 2017 की अवधि के लिए बीमा कराया था।

चाहिए। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए दिए। एक राजनीतिक दल किसी प्राइवेट बॉडी को लोन नहीं दे सकती यह स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का राइट ऑफ हो जाना और करोड़ों की संपत्ति एक अनजानी सी कंपनी के हाथ चले जाना क्या यह गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ? इस कंपनी के 76 फीसदी शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास जाते हैं और 9 करोड़ के इन्वेंट्री शेयर महज 50 लाख में डाइस्फर कर दिए जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। डोटासरा और कन्हैया कुमार को यंग इंडिया कंपनी के कार्यों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

जयपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में सफाई देते हुए प्रेसवार्ता करने पर पटलवार करते हुए कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग के सरगनाओं में शुमार कन्हैया कुमार अब देश के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। जिस कन्हैया कुमार को राष्ट्र के प्रति निष्ठा, लोकतंत्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता संदिग्ध हो, वो कन्हैया कुमार अब गांधी नेहरू परिवार की चरण चाटुकारिता के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। डोटासरा, कन्हैया कुमार जैसे लोग बस एक परिवार की

- ‘डोटासरा और कन्हैया कुमार जैसे लोग आज भी एक परिवार की कर रहे हैं खिदमत’

खिदमत के अलावा कुछ ओर नहीं कर सकते। डोटासरा और कन्हैया कुमार किस हैसियत से सवाल कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को देश के प्रति निष्ठा और भारतीय संविधान के प्रति सम्मान देशवासी जेएनयू के प्रदर्शन में देख चुके है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय सरकार, न्यायपालिका और रक्षा, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों जैसे सभी महत्वपूर्ण अंगों की

विश्वसनीयता पर हमला देश कभी बदरिश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्यों को बेहतर ढंग से समझना चाहिए कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा पर निकल पड़ा है। हम भारत के लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है।

गोठवाल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जनरल लोन नहीं चुका पाई तो कॉर्पोरेट षड्यंत्र का के गांधी परिवार के पास संपत्ति आ जाए इसके लिए यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया कंपनी समाज सेवा नहीं करती है। यह तो कन्हैया और डोटासरा को पता होना

चाहिए। 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए दिए। एक राजनीतिक दल किसी प्राइवेट बॉडी को लोन नहीं दे सकती यह स्पष्ट नियमों का उल्लंघन है। 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का राइट ऑफ हो जाना और करोड़ों की संपत्ति एक अनजानी सी कंपनी के हाथ चले जाना क्या यह गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ? इस कंपनी के 76 फीसदी शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास जाते हैं और 9 करोड़ के इन्वेंट्री शेयर महज 50 लाख में डाइस्फर कर दिए जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। डोटासरा और कन्हैया कुमार को यंग इंडिया कंपनी के कार्यों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

- हजारों रुपए का लकड़ी का कचरा व प्लाइवूड खाक
- अग्निशमनकर्मियों ने दो घण्टे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

लकड़ी का कचरा राख हो गया। बाद में आग लगने की सूचना पर मिलने पर चौमूं, कालाडेरा व मण्डा रीको औद्योगिक क्षेत्र से पहुंची चार दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया।

प्रथमदृष्ट्या आग लगने का कारण शॉट सक्रिट माना जा रहा है। चौमूं अग्निशमन अधिकारी जय कुमार जाँगिड ने बताया कि सोमवार सुबह



जयपुर ग्रामीण जिले के कालाडेरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार अल सुबह अचानक प्लाइवुड फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखी हजारों रुपए की प्लाइवुड व लकड़ी का कचरा राख हो गया।

औद्योगिक क्षेत्र स्थित खादूरग्राम वृड इण्डस्ट्रीज में रखे लकड़ी के कचरे में अचानक आग लग गई। आग ने देखते-देखते हुए विकराल

रूप ले लिया। बाद में फैक्ट्री कार्मिकों ने इसकी जानकारी कालाडेरा रीको अग्निशमन केन्द्र में दी। इस पर चौमूं, कालाडेरा व मण्डा रीको औद्योगिक क्षेत्र

से पहुंची चार दमकलों ने दो घण्टे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संभवतः आग लगने का कारण शॉट सक्रिट माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल आपूर्ति के लिए बने मलसीसर डैम का निरीक्षण किया

शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पानी हमारी प्रमुख प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

झुंझुनूं/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को झुंझुनूं जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल आपूर्ति के लिए बने मलसीसर डैम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पेयजल तथा खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हम प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के संकल्प को साकार करते हुए जनता से किया हर एक वादा पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही सबसे पहले यमुना जल को शेखावाटी में लाने के लिए हरियाणा सरकार से यमुना जल समझौते पर एमओयू किया। इस समझौते की क्रियान्विति सुनिश्चित हो रही है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। उन्होंने शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश डालते हुए यहां के रणबांकुरों के प्रति श्रद्धा व सम्मान जताया। मुख्यमंत्री ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मलसीसर डैम का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय संरचना का शिलान्यास व पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास की बात करते हैं। यही कारण है कि अब ना तो चुनाव है, फिर भी तपती गर्मी में आपके बीच आए हैं। बात भी कर रहे हैं। समस्या भी सुन रहे हैं। सीएम ने सभी से अपील की कि वे नकली लोगों से बचकर रहें। जब यमुना का पानी शेखावाटी की धरती

पर आएगा, तो ना केवल शेखावाटी, बल्कि राजस्थान और पूरा देश विकसित होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरि, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार की अगुवाई में स्वागत किया गया। मंच पर झुंझुनूं विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश

दाधीच, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वभर पुनियां, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया, सूरत प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल खीचड़, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉ. राजेश बाबल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम्रेन्द्र चारण, पूर्व प्रधान विमला चौधरी, दिनेश राजपुरोहित आदि मौजूद थे। यहां से मुख्यमंत्री मलसीसर में बनाए गए

- सीएम ने शेखावाटी की सांस्कृतिक विरासत पर भी प्रकाश डालते हुए यहां के रणबांकुरों के प्रति श्रद्धा व सम्मान जताया

कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के डैम पहुंचे। जहां पर उन्होंने डैम में स्टोर किए गए पानी और उसके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि नहरबंदी और गर्मी के दौरान पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आन्धान पर सूरत प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम और उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर अभियान के तहत मलसीसर में एक रिचाजैबल ट्यूबवैल की पूजा-अर्चना कर उसका कार्य आरंभ किया। जमीन में वापिस पानी पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सीएम ने प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम और उनके साथ लगे सभी प्रवासियों को इसके लिए बधाई दी।

कॉलोनी के बीच शराब ठेका खोलने का विरोध तेज



भीलवाड़ा शहर के श्याम विहार कॉलोनी के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की श्याम विहार कॉलोनी के बीच शराब ठेका खोलने का विरोध अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। स्थानीय लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के श्याम विहार कॉलोनी में शराब ठेका खोलने को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, पिछले 15 दिन से चल रहे विरोध के बाद कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्री की और कूच करते हुए पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में

- स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया**

- अवस्थी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे**
- जिला कलेक्ट्री कार्यालय पहुंचे प्रदर्शन किया।

ज्ञापन में उन्होंने बताया कि श्याम विहार कॉलोनी में पहले से ही दो शराब ठेके चल रहे हैं और एक और ठेका खुलने से क्षेत्र का सामाजिक वातावरण दूषित होगा।

उन्होंने आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग इस क्षेत्र को शराब की मंडी बनाना चाहता है, जिसे कॉलोनीवासी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्षेत्रवासियों ने दो दिन के भीतर अवैध शराब ठेके को बंद करने की मांग की है। पूर्व विधायक अवस्थी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।

दो भाइयों पर जानलेवा हमला कर अपहरण के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने दो भाइयों पर लाठियों, सरियों से जानलेवा हमला कर कार में तोड़फोड़ करने व अपहरण कर ले जाने के दो आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने बताया कि 3 अप्रैल 2015 को एमजी अस्पताल में फागणों का खड़ा निवासी लादूलाल पुत्र स्व. दीपा गुर्जर ने कोतवाली पुलिस को बयान दिया कि आज सुबह 11 बजे वह और उनकी मौसी का बेटा भोजराज सफारी गाड़ी लेकर भीलवाड़ा रवाना हुये। रास्ते में हरणी महादेव चौराहे पर रुके, जहां भोजराज के बोरिंग वाहन के स्ट्रफ का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद वे भीलवाड़ा की ओर रवाना हो गये। स्विफ्ट कॉलेज, बड़ला चौराहा रोड पर चाय की केबीन पर रुके, जहां परिवादी गाड़ी में बैठा था, जबकि भोजराज चाय पी रहा था। इसी दौरान

- दोनों आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 9-9 हजार के अर्थदंड से दंडित किया**

रतन, भगवान, सांवरा, रामेश्वर व इनके साथ 8-10 अन्य लड़कों ने परिवादी लादूलाल पर टापी, सरियों से मारपीट शुरू कर दी। सांवरमल व रामेश्वर ने टापी से हमला किया। गाड़ी पर भी सरिये व लाठियों मारी, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। परिवादी लादू व उसके भाई भोजराज को गाड़ी में किडनैप पर आरोपित सुवाणा की ओर ले गये, जहां रास्ते में भी परिवादी से मारपीट की गई। ये आरोपित कह रहे थे कि रास्ते में ईरांस में इसे कुएं में डाल दो। ईरांस क्षेत्र में गाड़ी बंद होने पर वह चिल्लाया तो आरोपितों ने उस पर पथर मारे। गांव वालों के आ-जाने से आरोपित भाग छुटे। लादूलाल ने बयान में बताया कि

सूरतगढ़ थर्मल कॉलोनी में खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ों की कटाई

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां सूरतगढ़ थर्मल कॉलोनी में हाल ही में खेजड़ी के कई हरे-भरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवनदायिनी मानी जाने वाली खेजड़ी न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसे में इन पेड़ों की कटाई ने आमजन, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों को चिंतित कर दिया है। साथ ही इससे

- सामाजिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की**

लोगों में नाराजगी भी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, कॉलोनी के कुछ हिस्सों में विकास कार्य के नाम पर खेजड़ी के दर्जनों पेड़ों को बिना किसी ठोस वैधानिक अनुमति के काट दिया

गया। यह न केवल वन संरक्षण अधिनियम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार इस अवैध कटाई में शामिल पाए जाये, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये। पर्यावरण प्राणियों ने बताया कि यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो सूरतगढ़ जैसे अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन और हरियाली की कमी का संकट और गहराता जाएगा।

संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार इस अवैध कटाई में शामिल पाए जाये, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये। पर्यावरण प्राणियों ने बताया कि यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो सूरतगढ़ जैसे अर्द्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन और हरियाली की कमी का संकट और गहराता जाएगा।

शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग

भीलवाड़ा, (निसं)। जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर किसान केसरी संघ के बैनर तले चारमील दौलतपुर के किसान शक्तिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को दिया।

चारमील दौलतपुर के किसान के किसान केसरी संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, उपाध्यक्ष रज्जाक मोहम्मद, भंवर माली, सांवरलाल वैष्णव, सांवरा खारोी, महावीर कुमावत, छोटू कुमावत, गणपत बैरवा, सोहन कुमावत, प्रहलाद लोहार, पुष्पेंद्र खटीक, हीरा कुमावत, भैरू गाडरी, राधेश्याम सहित कई सदस्य क्रमिक अनशन धरने पर बैठे। धरने को किसान केसरी संघ के जिला अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ओझा, उपाध्यक्ष रज्जाक मोहम्मद, महावीर कुमावत, सांवरलाल, भंवर माली, रामप्रसाद जाट, महासचिव कमलेश मुंडेरिया, सदस्य सुरेश चन्द्र घूसर, रामप्रसाद सेन ने संबोधित करते हुए सरकार से शाहपुरा जिले की बहाली की मांग की।



विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विभिन्न विकास कार्यो का शुभारम्भ किया।

पर हरी नगर और दाता नगर स्थित पुराने कुओं पर सुरक्षा हेतु लगाए गए लोहे के जालका लोकाण किया। पार्क नंबर 2 सहित अन्य पार्कों में बच्चों के झूलों के पुनर्निर्माण कार्य को भी जनता को समर्पित किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 20 लाख रुपए की लागत से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास डामर सड़क निर्माण

- अजमेर, (कासं)।** विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम अजमेर को सुविकसित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अजमेर उत्तर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नसीराबाद से नौसर पाहप लाइन तथा तीन सर्विस रिजर्वायर बनाने के लिए 270 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। इसके साथ ही अजमेर को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, खेल, सड़क और बिजली आदि के क्षेत्र में विकसित बनाने की भी सैकड़ों करोड़ रूपए खर्च होंगे। इसके लिए योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अजमेर राज्य के बड़े शहरों की कतार में आगे खड़ा दिखेगा।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को वार्ड 66 के सामुदायिक भवन, पार्क नंबर 2 में आयोजित समारोह में क्षेत्र में पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यो का शुभारम्भ किया। उन्होंने वाचनालय, सीसी सड़कों, नलियों, झूलों और कुओं पर लोहे के जालकार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर

- अजमेर की जल व्यवस्था सुदृढ़ होगी, 270 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी : देवनानी**
- मुख्यमंत्री भजनलालशर्मा ने बजट में अजमेर को कई सीमांत दी हैं। उन्होंने कहा कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पतालके भवन का 50 करोड़ रूपए की लागत से जीर्णोद्धार तथा उन्नयन कार्य, हाथीभाटा में 132 केवी जीएसएम की स्थापना, अजमेर संभाग मुख्यालय पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर, जिला अस्पताल में डेडीकेटेड गेरियाट्रिक सेंटर रामाश्रय का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही गंगा बैरव घाटी काजीपुरा में लेपर्ड कंजर्वेशन की स्थापना तथा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मंडलअध्यक्ष रचित कच्छावा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

- अजमेर की जल व्यवस्था सुदृढ़ होगी, 270 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी : देवनानी**

मुख्यमंत्री भजनलालशर्मा ने बजट में अजमेर को कई सीमांत दी हैं। उन्होंने कहा कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पतालके भवन का 50 करोड़ रूपए की लागत से जीर्णोद्धार तथा उन्नयन कार्य, हाथीभाटा में 132 केवी जीएसएम की स्थापना, अजमेर संभाग मुख्यालय पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर, जिला अस्पताल में डेडीकेटेड गेरियाट्रिक सेंटर रामाश्रय का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही गंगा बैरव घाटी काजीपुरा में लेपर्ड कंजर्वेशन की स्थापना तथा अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मंडलअध्यक्ष रचित कच्छावा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन एक मिसाल है- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राठौड़ ने कहा, यह जन्म दिन का उत्सव नहीं, प्रधानमंत्री के आह्वान के संकल्प का समागम है

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ईआरसीपी, गंग नहर तथा यमुना समझौता- सभी के कार्य ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

चूरू / जयपुर, 21 अप्रैल। चूरू जिले के पुलिस लाइन मैदान में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित “संकल्प दिवस समारोह” में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजनीति जनता के कल्याणकारी कार्यों से होती है। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन राजनीति में एक मिसाल है। उनके जन्मदिन पर “एक पेड़ माँ के नाम” का संकल्प कार्यकर्ताओं व आमजन के द्वारा लेना एक अनुकरणीय प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने पूरे राजस्थान में पानी के लिए कार्य किया है। चाहे ईआरसीपी हो, गंग नहर हो या यमुना समझौता हो, सभी कार्य ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब हरियाणा में चुनाव आया तो वहां की कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान से यमुना का समझौता हम रद्द कर देंगे। उस घोषणा पत्र को जारी करते समय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के जन्म दिवस पर चूरू में आयोजित “संकल्प दिवस समारोह” को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ का सार्वजनिक जीवन राजनीति में एक मिसाल है।

कहा कि यह आयोजन इस बार भी जन्मदिन उत्सव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के संकल्प का समागम है। इसी को लेकर कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक वर्ष में 100 पेड़ लगाने, शेखावाटी में सामाजिक बुराई बाल विवाह व श्रृण हत्या को रोकने,गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने प्राकृतिक जल स्रोतों, जोहड़, बावड़ी, जो गांव में बनी

हैं, उसके संरक्षण का और बेटियों को शिक्षित करने का संकल्प लिया। राठौड़ ने कहा, उनका जन्मदिवस प्रतिवर्ष संकल्प दिवस के रूप में समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत व

गौतम दक , हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडीमंत्री रणवीर गंगवा जी,हिसार के नलवा से विधायक रणधीर पनिहार , चूरू विधायक हरलाल सहारण , डींग-कुम्हर विधायक डॉ.शैलेश सिंह , नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा , चूरू लोकसभा से पश्चिमभूषण देवेंद्र झाझड़िया , पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

पोप फ्रांसिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सात बजकर 3.5 मिनट पर कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे।पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें 14 फरवरी को रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका निमोनिया और एनीमिया का इलाज भी चल रहा था। वह पांच हफ्ते तक फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती थे।

इलाज के दौरान कैथलिक चर्च के हेडक्वार्टर, वैंटिकन ने बताया था कि पोप की रक्त जांच रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। साथ ही रक्त में प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। चौदह मार्च को हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी।सत्रह दिसंबर 1936 को जन्मे पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक जेसुइट पादरी थे। वे 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। उन्हें पोप बनेडिक्ट सोलहवें का उत्तराधिकारी चुना गया था। पोप फ्रांसिस बीते 1000 साल में पहले ऐसे ईसान थे जो गैर-यूरोपीय होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे।

गहलोत सरकार का कोविड प्रबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गौर फरमाने योग्य है कि कोविड महामारी के दौरान एस.डी.आर.एफ. के उपयोग से मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी धांधली का पुख्ता प्रमाण इन प्रकाशित दस्तावेजों में देखा जा सकता है, जहां एस.एम.एस. अस्पताल में मात्र साढ़े नौ लाख रुपये में एक वैंटिलेटर की खरीद की जा रही थी और केवल 5 प्रतिशत जी.एस.टी.दिया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में 1एक वैंटिलेटर 16 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का खरीदा गया, कुल 11 वैंटीलेटर खरीदे गए और इन पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. भी लगा, यानि 200 प्रतिशत से भी अधिक कीमत दी गई।

इस पूरे प्रकरण में एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति और बीकानेर के एस पी मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति के वित्तीय सलाहकारों की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठते हैं कि उन्होंने सभी सरकारी अस्पतालों के मेडिकल कॉलेजों से उनकी जरूरत अनुसार मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये प्रस्ताव क्यों नहीं मांगे। और फिर एक साथ “बल्क” में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिये आदेश क्यों नहीं जारी किये गये, जिससे उन्हें किफायती दरों पर अच्छे मेडिकल उपकरण मिल जाते, परंतु गहलोत सरकार के अधिकारियों ने इस नीति को ना अपनाते हुए अलग-अलग अस्पतालों में गैर कानूरी तरीके से बने आई.सी.यू. के लिए मेडिकल उपकरणों की खरीद के अलग-अलग आदेश दिये, जिनमें भारी धांधली की गई और मित्र कंपनियों को खुश रखने के लिये भारी दरों पर जी.एस.टी. का भुगतान किया गया।

पाठकों को बता दें कि एस.डी.आर. एफ. राज्य सरकार को हर वर्ष केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है, यानी केंद्र सरकार के दिये गये फंड में प्रदेश में अफसरों की मदद से डेफरेंसी की गई, इसलिये उचित यही है कि इस घोटाले की जांच भी केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ही करें।

SUMITRA ENTERPRISES		
Bhadasiya Fruit and Vegetable Market, Opp G.S.S. Bhadasiya, JODHPUR342016 sumitraenterprises0291@gmail.com. Contact No. 9460957429		
List of equipment and other part of supply order no 902 Dt. 10/08/2021		
S.No.	Equipments Name	Qty Amount
1	X ray view Box	3 33,000.00
2	Biphasic defibrillator	3 7,86,666.00
3	ECHO Machine	1 24,00,000.00
4	USG 4 D colour Doppler	1 25,00,000.00
5	Portable X ray	2 9,60,000.00
6	Bipap Machine	5 5,25,000.00
7	ICU beds with mattress	50 48,68,000.00
8	Multipara monitor with	50 95,96,000.00
9	Syringe pump	50 24,60,000.00
10	Transport Ventilator	2 9,60,000.00
11	ABG Machine	3 27,30,000.00
12	POC Analyzer	3 6,75,000.00
13	ICU Ventilator	1 1,77,80,000.00
14	Video laryngoscope	3 5,70,000.00
15	ICU Resuscitator Kit	5 14,00,000.00
16	ICU Decontamination System	5 15,75,000.00
17	Air way clearance system	3 26,90,000.00
18	Crash Cart	2 2,34,000.00
19	Bed Side Cardiac Table	50 1,75,000.00
20	Bed Side Locker	50 1,60,000.00
21	Attendant Table	50 75,000.00
22	Medicine Trolley	3 41,500.00
23	Patient Stretcher	3 38,000.00
24	Suction Machine	4 88,000.00
25	ECG Machine	2 2,08,000.00
26	Almirah	3 36,000.00
27	BK Capacity Fridge	3 65,000.00
28	Wall mounted shelves	3 30,000.00
29	Cup Board	3 48,000.00
30	Curtains	As per Site Requirement 5,40,000.00

For SUMITRA ENTERPRISES For SUPPLY		
31	Table for Nursing work station	3 9000.00
32	Change Locker	3 42,000.00
33	Shoe Racks	5 30,000.00
34	Corner Table	5 19,500.00
35	White Marker Board	3 38800.00
36	CCTV	As per site 3000.00
37	Bougie	2 42,000.00
38	Furniture for ICU (Chair, Bed, Table)	1 Each 5,41,40,800.00
39	Total Value of Equipment	1,98,91,200.00
40	MGPS & Construction Part	7,40,32,000.00
41	Total Value of 50 Bedded ICU on Turn Key	

For SUMITRA ENTERPRISES Proprietor

प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित दस्तावेज नम्बर (1) में देखा जा सकता है कि एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में क्रय समिति ने लगभग नौ लाख रुपये की दर से आठ आई.सी.यू. वैंटिलेटर खरीदे। वहीं अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित सुमित्रा एन्टरप्राइजेज के सम्पूर्ण बिल (एन्ट्री नं. 13) में देखा जा सकता है, कि बीकानेर में 11 वैंटिलेटर लगभग 16 लाख रुपये की दर से खरीदे गये। जिससे साफ जाहिर है कि इन मेडिकल कॉलेजों की क्रय समिति में कार्यरत सरकारी वित्त सलाहकारों ने अलग-अलग दरों पर वैंटिलेटर खरीदे जबकि उन्हें प्रदेश में सभी अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए वैंटिलेटरों की “बल्क” में खरीद के आदेश देने चाहिये थे, जिससे उन्हें किफायती दर मिलती।

‘वैस की भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भिन्न आर्थिक लक्ष्यों को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ अमेरिका अपने व्यापार के उत्थान के लिये टैरिफ का उपयोग हथियार के रूप में कर रहा है, वहीं भारत का फोकस अपने उद्योगों के संरक्षण पर तथा नियमाधारित निष्पक्ष व्यापार करने पर बना हुआ है।

वांग ने कहा कि वैस भले ही भारत को चीन के महींगे होते जा रहे आयातों के संभावित विकल्प के रूप में देख रहे हों, लेकिन भारत की वर्तमान सप्लाई चेन क्षमताएँ चीन की क्षमता और निपुणता एवं कुशलता की बराबरी नहीं कर सकती। इसके अलावा, भारत से आयातों को बढ़ाना अमेरिका के उन प्रयासों के प्रतिकूल रहेगा, जो अमेरिका व्यापार घाटा कम करने तथा उद्योगों को अपने देश में लाने की दिशा में कर रहा है। उन्होंने वैस के उपरोक्त संभावित प्रयासों को अन्तर्विरोधी बताया।

चीनी विशेषज्ञों ने भारत को सचेत किया है कि वह व्यापारिक प्रस्तावों के पर्दे में छिपे वॉशिंगटन के “अमेरिका फस्ट” के सिद्धांत के प्रति सजग एवं चौकन्ना रहे। कियान ने निष्कर्ष के रूप में कहा कि भारत का सर्वोत्तम हित अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने और बनाये रखने में तथा अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करने में तथा उन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में निहित है, जो खुले और बराबरी के व्यापार के लिये ईमानदारी के साथ संकल्पित है।

सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्कर नाज़िम खान की जमानत रद्द की

जयपुर, 21 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्करी से जुड़े मामले में, आरोपी व आदतन अपराधी नाज़िम खान को 21 अक्टूबर 2024 को दी गयी जमानत के आदेश को वापस लेकर उसकी जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

मामले से जुड़े राज्य सरकार के एग्जी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च अदालत ने 21 फरवरी को इस मामले में यूपी सरकार को पक्षकार बनाते हुए, उसे निर्देश दिया था कि वह आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी पेंडिंग केसों की लिस्ट व उसकी फरारी के संबंध में रिपोर्ट पेश करे। वहीं, आरोपी नाज़िम खान को भी शपथ पत्र पेश कर उसके खिलाफ पेंडिंग केसों का ब्यौरा देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में राज्य सरकार की लापरवाही और किसी के उपस्थित नहीं होने के चलते, 21 अक्टूबर, 2024 को आरोपी को जमानत दे दी गयी थी। राज्य सरकार ने जमानत आदेश को वापस लेने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। राज्य सरकार का

■ अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

कहना था कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम, गोवध कानून और हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से वह 5 मामलों में भगोड़ा घोषित हो चुका है और उसके गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा केस में भी वह तीन साल से फरार था और अप्रैल 2024 में उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहां पर भी वह गौ तस्करी केस में ही बंद था। इसलिए आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाए। आरोपी के खिलाफ करौली जिले के नौदौती में 13 फरवरी 2021 को गौ तस्करी की रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। इसमें कहा गया था कि एक कंटेनर में वह गौवंश की तस्करी कर रहा था।

जयपुर कलैक्टर हाउसिंग बोर्ड से हर्जाना वसूल करें

जयपुर, 21 अप्रैल। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने जयपुर कलेक्टर को कहा है कि वे एक प्रकरण में आवासन मंडल पर लगाए गए हर्जाने की वसूली कर आयोग को उसकी जानकारी पेश करें। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मोना ने यह आदेश पीबी जैन की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परिवारी ने सिरोही में आवास आवंटित करने के लिए साल 1983 में आवासन मंडल में पंजीयन राशि जमा करवा कर पंजीकरण कराया था। अगले साल मंडल ने आवेदन कम होने का हवाला देकर पंजीयन राशि वापस लेने को कहा। इसके बाद,

■ जिला उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को परिवारी के रुपये वापस करने के साथ 3.10 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा था।

में कहा गया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने 21 सितंबर, 2009 को आवासन मंडल को निर्देश दिए थे कि वह मई, 1996 की लागत से परिवारी को भीलवाड़ा में एमआईजी का आवास आवंटित करें। आवास उपलब्ध नहीं होने पर परिवारी को दस लाख रुपए अदा करने को कहा गया था। इसके अलावा, आयोग ने मंडल पर 3.10 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया था। आदेश की पालना नहीं होने पर, परिवारी ने आयोग में वसूली प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश की पालना की गुहार की। मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग ने जिला कलेक्टर को वसूली कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री



धरती ही हमारा धन

इसका करें संरक्षण

पृथ्वी दिवस

22 अप्रैल, 2025

आइये , इस अवसर पर हम सब मिलकर भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण को प्रदूषण मुक्त करें,अपने आसपास स्वच्छता रखें एवं धरती को हरा-भरा, सुंदर बनाने का संकल्प लें।

पर्यावरण विभाग, राजस्थान